लखनऊ

शुक्रवार, 18 जुलाई, 2025

वर्ष : 11 । अंक: 9

मूल्य : 1 रुपये

पृष्ठ : 8

हिंदी दैनिक

आर्यावर्त क्रांति

UPHIN/2014/57034

हम जब तक खुद मां बाप नहीं बन जाएं, मां बाप का प्यार कभी नहीं जान पाते। - हेनरी वार्ड बीचर

TODAY WEATHER

DAY 37° Hi

NIGHT 26° Low

संक्षेप

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल; ईडी की चार्जशीट में कई और नाम

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में आरोप पत्र दायर कर दिया है। इसमें कई अन्य व्यक्तियों और कंपनियों के नाम भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक, ईडी ने शिकोहपुर भूमि सौदा मामले में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ एक पूरक अभियोजन शिकायत दायर की है। मामला सितंबर 2018 का है, जब सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा, हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ और एक प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर में भ्रष्टाचार, जालसाजी और धोखाधड़ी सहित अन्य आरोप लगाए गए हैं। वाड्रा पर आरोप हैं कि उनसे जुड़ी कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज से 7.5 करोड़ रुपये में 3.5 एकड़ जमीन खरीदी थी। इस सौदे का म्यूटेशन भी असामान्य तरीके से कर दिया गया। आरोप है कि हरियाणा के तत्कालीन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने इस जमीन में से 2.70 एकड़ जमीन को कमर्शियल कॉलोनी के तौर पर डेवलप करने की इजाजत देते हुए रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी को इसका लाइसेंस दिया था। आवासीय परियोजना का लाइसेंस मिलने के बाद जमीन की कीमत बढ़ गई। बाद में वाड्रा से जुड़ी कंपनी ने कंपनी ने ये जमीन डीएलएफ को 58 करोड़ में बेच दी। आगे चलकर हुड्डा सरकार ने आवासीय परियोजना का लाइसेंस डीएलएफ को ट्रांसफर कर दिया। आरोप है कि इस पूरी डील में कई अनियिमताएं की गई। हरियाणा पुलिस ने 2018 में इस सौदे से जुड़े मामले में केस दर्ज किया। आगे चलकर ईडी ने भी इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू की।

चंदन मिश्रा हत्याकांड में अस्पताल कर्मियों से होगी पूछताछ, आईजी बोले- अपराधियों को किया जा रहा चिन्हित

पटना। बिहार की राजधानी पटना के पारस अस्पताल में भर्ती चंदन मिश्रा की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना को लेकर आईजी जितेंद्र राणा का बयान आया है। उन्होंने बताया कि अपराधी चंदन मिश्रा हाल ही में इलाज के लिए जेल से पैरोल पर बाहर आया था। इसी दौरान कुछ अपराधियों ने उस पर हमला कर दिया। आईजी जितेंद्र राणा ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत में बताया, बक्सर जिले का एक बड़ा अपराधी चंदन मिश्रा हाल ही में इलाज के लिए जेल से पैरोल पर बाहर आया था। ऐसा प्रतीत होता है कि यह घटना या तो आपसी झगड़े या विरोधी गिरोहों के कारण हुई। इलाज के दौरान ही कुछ अपराधियों ने उस पर हमला किया और उसे कई गोलियां मारी हैं। इस बारे में अधिक जानकारी डॉक्टर ही साझा करेंगे। उन्होंने आगे कहा, चंदन मिश्रा एक बड़ा अपराधी था, और पुलिस पता लगा रही है कि उसे गैंगवॉर के चलते गोली मारी गई है या इस हमले का कोई और कारण है। हम इस घटना के बारे में पता लगा रहे हैं और इसमें शामिल अपराधियों को चिन्हित किया जा रहा है। मामले को लेकर बक्सर पुलिस के साथ भी संपर्क में हैं। आईजी जितेंद्र राणा ने घटना में अस्पताल के कर्मचारियों के

धमकाकर जमीन बेचने के लिए मजबूर किया, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका

नई दिल्ली, एजेंसी। एक व्यक्ति को बंदूक के दम पर डराकर उसे जमीन बेचने के लिए मजबूर करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने याचिकाकर्ताओं ललित मोहन राय और ललित राय की याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ताओं के वकील से कहा कि आपके मुवक्किल गुंडे लग रहे हैं।

दरअसल याचिकाकर्ताओं ने साल 2023 में 60 खाता जमीन को धोखाधड़ी से खरीदा और जमीन के मालिक को बंदूक के दम पर डराकर उसके हस्ताक्षर कराए गए। इस मामले में 26 नवंबर 2023 को पटना के गांधी मैदान पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। आरोपियों ने इसके खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की और अग्रिम जमानत देने की अपील की। हालांकि उच्च न्यायालय ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दोनों आरोपी सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन अब वहां से भी उन्हें निराशा हाथ लगी है।

रूसी महिला के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी

चार साल के बच्चे की कस्टडी से जुड़े एक विवाद में, सुप्रीम कोर्ट ने विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय को एक रूसी महिला का पता लगाने के लिए लुकआउट नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। महिल कथित तौर पर अपने चार साल के बच्चे को लेकर फरार हो गई है। यह बच्चा विवाहेतर संबंधों से पैदा हुआ था। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर और डिफेंस कॉलोनी पुलिस स्टेशन के SHO को बिना समय गंवाए लापता बच्चे का पता लगाने और उसकी कस्टडी प्रतिवादी को सौंपने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय अधिकारियों को रूसी महिला का पासपोर्ट जब्त करने का भी निर्देश दिया है और एयरपोर्ट और माइग्रेशन अथॉरिटीज को देश भर के सभी एयरपोर्ट्स के प्रवेश और निकास पर नजर रखने का निर्देश दिया है।

यमुना वाटिका और बांसेरा पार्क पहुंचे उपराष्ट्रपति, कही यह बड़ी बात

नई दिल्ली, एजेंसी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को दिल्ली में यमुना वाटिका और बांसड़ा पार्क का दौरा किया, जहां उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने उनका स्वागत किया। धनखड़ ने भारत की तेज़ आर्थिक वृद्धि और राजधानी में विकास कार्यों की सराहना की। उन्होंने उपराज्यपाल वीके सक्सेना के प्रयासों की भी सराहना की और दिल्ली में उनके काम को क्रांतिकारी बताया और कहा कि रिवरफ्रंट एक प्रमुख वैश्विक आकर्षण बनेगा। पत्रकारों से बात करते हुए, धनखड़ ने कहा कि दिल्ली भारत की राजधानी है। उपराज्यपाल विनय सक्सेना द्वारा किया गया कार्य क्रांतिकारी है। दिल्ली के लोग हमेशा याद रखेंगे कि उनके प्रयास फल दे रहे हैं। दिल्ली को नए फेफड़े, नई ऊर्जा प्रदान की जा रही है।

वाराणसी में गंगा का रौद्र रूप : घाट जलमग्न, प्रशासन ने लोगों को किया सचेत

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

वाराणसी। उत्तर भारत में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में साफ दिखाई दे रहा है। धार्मिक नगरी काशी में मां गंगा उफान पर हैं, जिसके चलते वाराणसी के प्रसिद्ध 84 घाटों में पानी भर गया है। कई घाट पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं, और घाटों के किनारे बने मंदिरों में भी पानी घुस गया है।

खास तौर पर अस्सी घाट, जो पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहा है, पूरी तरह डूब चुका है। यहां हर सुबह होने वाला 'सुबहे बनारस' का मंच भी गंगा की लहरों में समा गया है। स्थानीय प्रशासन ने गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए लोगों को गहरे पानी में न जाने की चेतावनी दी है। घाटों पर लगातार मुनादी की जा रही है और छोटी-बड़ी सभी नौकाओं के संचालन पर रोक लगा दी गई है। गंगा का जलस्तर वर्तमान में 68.94 मीटर पर पहुंच चुका है, जो चेतावनी निशान 70.262 मीटर के करीब है। खतरे का निशान 71.262 मीटर है, और जलस्तर 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। यदि यह गति बरकरार रही, तो आने वाले दिनों में निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। स्थानीय निवासी राकेश पांडेय ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में बताया, पानी में बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन फिलहाल स्थिर है। कोई नहीं बता सकता कि पानी बढ़ेगा या घटेगा।

क्या भाजपा की इलेक्शन चोरी शाखा बन चुका है ईसी ? राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर वार

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को दावा किया कि चुनाव आयोग बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के नाम पर वोट चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। उन्होंने पूछा कि क्या चुनाव आयोग पूरी तरह से भाजपा की 'चुनावी चोरी शाखा' बन गया है। वहीं, चुनाव आयोग हमेशा से कहता रहा है कि 22 साल बाद हो रहे इस पुनरीक्षण से मतदाता सूची से अपात्र लोगों और डुप्लिकेट प्रविष्टियों को हटाया जाएगा और कानून के अनुसार मतदान के पात्र लोगों को भी शामिल किया जाएगा।

राहुल गांधी ने एक्स पर एक वीडियो साक्षा करते हुए लिखा कि बिहार में चुनाव आयोग 'SIR' के नाम पर रंगे हाथ वोट चोरी करता पकड़ा गया। काम सिर्फ़ चोरी, नाम 'SIR' - पर्दाफाश करने वाले पर होगी FIR ! EC अब भी 'Election Commission' है या पूरी तरह BJP की 'Election Chori' शाखा बन चुका है? वहीं, कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा कि नागरिकता प्रमाणित करना निर्वाचन आयोग का काम नहीं है तथा विशेष गहन पुनरीक्षण के नाम पर राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) शुरू नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यह दावा भी किया कि अब आयोग अपने ही तर्कों में फंस गया है और 'मुद्दा भटकाओ योजना' के तहत नेपाल, म्यांमा और बांग्लादेश के लोगों के बिहार में होने की कहानी गढ़ रहा है।

कुमार ने कांग्रेस मुख्यालय 'इंदिरा भवन' में संवाददाताओं से कहा, ''यदि 2003 की पुनरीक्षण की प्रक्रिया गलत थी, तो उसके बाद के सभी चुनाव गलत हैं...क्या नरेन्द्र मोदी जी को म्यांमा और नेपाल के लोगों ने वोट दिया...अगर ऐसा है तो फिर बिहार के सभी 40 सांसदों को अयोग्य घोषित करिए और फिर से चुनाव करवाइए।'' कुमार ने एक सवाल के जवाब में कहा, ''क्या मतदाता सूची किसी राजनीतिक दल ने बनाया या निर्वाचन आयोग ने बनाया।

छांगुर बाबा पर कसा शिकंजा, धर्मांतरण केस में श्वष्ठ की बड़ी कार्रवाई ; यूपी–मुंबई के 14 ठिकानों पर की छापेमारी

नई दिल्ली/बलरामपुर/मुंबई, एजेंसी। धर्मांतरण केस में छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन पर शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में 12 और मुंबई में 2 ठिकानों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी गुरुवार सुबह 5.0 बजे शुरू हुई। ईडी की टीम एक साथ 14 ठिकानों पर जांच-पड़ताल कर रही है।

मुंबई में ईडी की टीमें खासकर शहजाद शेख के 2 आवासों पर छापेमारी की है। इनमें बांद्रा ईस्ट में कनकिया पेरिस की 20वीं मंजिल स्थित एफ विंग और माहिम वेस्ट में एलजे रोड, पीतांबर लेन, गैब्रियल बिल्डिंग के पास स्थित रिजवी हाइट्स सीएचएस के फ्लैट नंबर 502 शामिल हैं। छापेमारी के दौरान बांद्रा स्थित आवास पर मौजूद शहजाद शेख से ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी नवीन के बैंक खाते से शहजाद शेख के खाते में करीब दो करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ था।

श्वष्ठ धर्मांतरण और हवाला लेनदेन के इस मामले में छांगुर की महिला मित्र नीतू उर्फ नसरीन और नवीन के विभिन्न बैंक खातों की भी गहनता से जांच कर रही है। नीतू के कई बैंक खाते जांच के दायरे में हैं, जिनमें बैंक ऑफ इंडिया, पेटीएम बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एसबीआई के खाते शामिल हैं।

वहीं, नवीन के भारत स्थित कई बैंक खातों में करोड़ों रुपये के लेनदेन का पता चला है, जिनमें पेटीएम बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक के खाते शामिल हैं। जांच के दौरान नवीन घनश्याम रोहरा के नाम पर मौजूद विदेशी बैंक खातों के दस्तावेज भी श्वष्ठ के हाथ लगे हैं। इन खातों में एक्सिस बैंक , एसबीआई , एचडीएफसी बैंक , एक्सिस बैंक, अमीरात एनबीडी बैंक और फेडरल बैंक यूएई के खाते शामिल हैं। इसके अलावा, अल अंसारी एक्सचेंज का आईएनआर खाता और आईसीआईसीआई बैंक का एक विदेशी बैंक खाता भी श्वष्ठ की जांच के दायरे में है।

विदेश नीति पर पाकिस्तान जैसी भाषा बोलते हैं राहुल गांधी . . . किरेन रिजिजू का कांग्रेस नेता पर वार

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के मानसून सत्र से पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर कटाक्ष किया और उन्हें राष्ट्र-विरोधी या देश के खिलाफ कुछ भी न बोलने की सलाह दी। रिजिजू ने विदेश नीति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करने के पीछे गांधी की मंशा पर सवाल उठाया और कहा कि देश के लिए अच्छा काम करने में विपक्ष की भी भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी द्वारा देश की विदेश नीति पर प्रधानमंत्री की आलोचना करने से देश का भला नहीं होगा। देश के विकास में विपक्ष की भी भूमिका है। संसद में चर्चा होगी, लेकिन विदेश नीति पर दो राय नहीं होनी चाहिए।

लोकसभा में विपक्ष के नेता पर पाकिस्तान की भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जिस तरह से गांधी विदेश नीति पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, उससे देश को नुकसान होता है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान, हमने विदेश नीति को लेकर प्रधानमंत्री पर अलग से हमला नहीं किया।

बिहार में अब हर महीने 125 यूनिट बिजली फ्री, चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान

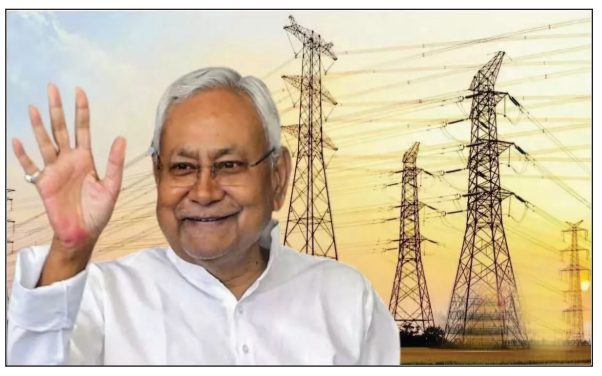

पटना, एजेंसी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आगामी विधानसभा चुनावों से पहले आम जनता को बड़ी राहत दी है। उन्होंने घोषणा की है कि 1 अगस्त 2025 से राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। उपभोक्ताओं को जुलाई माह के बिल से ही इसका लाभ मिलने लगेगा।

मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर जानकारी दी, हम लोग शुरू से ही सस्ती दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। अब तय कर लिया गया है कि घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली पर कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा।

इस योजना से करीब 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा, खासकर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को। इसके अलावा नीतीश कुमार ने कहा कि आने वाले तीन वर्षों में राज्य सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा देगी। उपभोक्ताओं की सहमति से घर की छतों या पास के सार्वजनिक स्थलों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे।

कुटीर ज्योति योजना के तहत अत्यंत निर्धन परिवारों के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। बाकी उपभोक्ताओं को भी सरकार द्वारा वित्तीय सहयोग दिया जाएगा। सरकार का अनुमान है कि इन प्रयासों से आने वाले वर्षों में राज्य को 10,000 मेगावाट तक सौर ऊर्जा मिल सकेगी, जिससे बिजली संकट काफी हद तक खत्म होगा।

मृतकों के आधार नंबर होंगे निष्क्रिय, यूआईडीएआई ने उठाया बड़ा कदम

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) अब ऐसे आधार नंबर बंद कर रहा है जो उन लोगों के हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, ताकि उनकी पहचान का गलत इस्तेमाल न हो सके। आधार नंबर एक 12 अंकों की खास पहचान होती है जो हर भारतीय नागरिक को दी जाती है। लेकिन किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका आधार नंबर बंद करना जरूरी हो जाता है ताकि कोई उसका गलत उपयोग न कर सके।

इस काम को आसान बनाने के लिए यूआईडीएआई ने 9 जून 2025 को 'माय आधारÓ पोर्टल पर एक नई सेवा परिवार के सदस्य की मृत्यु की सूचना शुरू की। इस सेवा के जरिए कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के मृत सदस्य की जानकारी देकर उनका आधार नंबर बंद करवाने के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए उन्हें अपनी पहचान साबित करनी होगी और मृत व्यक्ति का आधार नंबर, मृत्यु प्रमाण पत्र की जानकारी और अन्य विवरण देने होंगे। यह सुविधा फिलहाल 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हो चुकी है, बाकी राज्यों में भी जल्द शुरू होने की तैयारी है।

इसके अलावा, यूआईडीएआई ने भारत के महापंजीयक (आरजीआई) से आधार नंबरों से जुड़े मृत्यु रिकॉर्ड साझा करने का अनुरोध किया था। यूआईडीएआई के अनुरोध पर भारत के महापंजीयक (आरजीआई) ने अब तक 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (सीआरएस) के माध्यम से लगभग 1.55 करोड़ मृत्यु रिकॉर्ड दिए। उचित सत्यापन के बाद करीब 1.17 करोड़ आधार नंबरों को निष्क्रिय कर दिया गया है। गैर-सीआरएस राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ भी इसी तरह की प्रक्रिया जारी है। अब तक लगभग 6.7 लाख मृत्यु रिकॉर्ड मिल चुके हैं और उन्हें निष्क्रिय करने की प्रक्रिया चल रही है।

यूआईडीएआई मृतक आधार संख्या धारकों की पहचान करने में राज्य सरकारों की सहायता भी ले रहा है। एक पायलट परियोजना के तहत 100 साल से अधिक आयु वाले आधार धारकों का डेमोग्राफिक डेटा राज्यों को भेजा जा रहा है ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि आधार धारक जीवित हैं या नहीं। रिपोर्ट प्राप्त होने पर ऐसे आधार नंबर को निष्क्रिय करने से पहले जरूरी सत्यापन किया जाएगा। यूआईडीएआई की अपील है कि जब भी किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु हो जाए और मृत्यु प्रमाण पत्र मिल जाए, तो 'माय आधार' पोर्टल पर उनकी जानकारी जरूर दें, ताकि उनका आधार नंबर समय रहते बंद किया जा सके।

बाबा नीम करौली के भक्तों के लिए अच्छी खबर

नैनीताल से कैंची धाम तक बनेगा रोपवे, पर्यटन विभाग ने भेजा प्रस्ताव

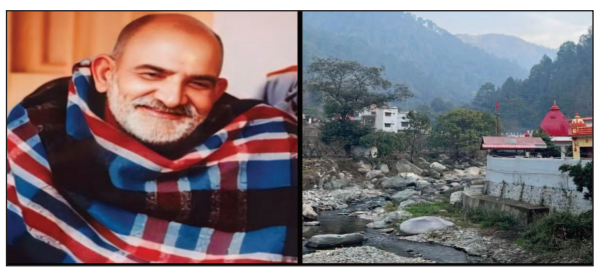

नैनीताल, एजेंसी। उत्तराखंड के नैनीताल आने वाले पर्यटकों और बाबा नीम करौली के भक्तों के लिए अच्छी खबर है। बताया जा रहा है कि नैनीताल से कैंची धाम की यात्रा जल्द ही रोपवे से हो सकेगी। जिला पर्यटन विभाग ने इस योजना का प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को भेजा है, जिसमें रूट, लागत, पर्यावरणीय प्रभाव और तकनीकी पहलू शामिल हैं।

नैनीताल से कैंची धाम की सड़क मार्ग से दूरी लगभग 17 किलोमीटर है। पर्यटन सीजन या वार्षिक मेले के दौरान इस मार्ग पर भीड़ और जाम की समस्या और भी बढ़ जाती है। ऐसे में रोपवे परियोजना श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए यात्रा को आसान और सुविधाजनक बनाएगी। नैनीताल की जिलाधिकारी वंदना सिंह ने कहा, नैनीताल से काठगोदाम तक रोपवे परियोजना पर पहले से ही विचार चल रहा है, इसकी डीपीआर तैयार है और यूटीडीबी के माध्यम से आगे की प्रक्रिया चल रही है। भवाली और कैंची धाम को रोपवे से जोड़ने के लिए एक और प्रस्ताव भेजा गया है। इसके पीछे का उद्देश्य यही है कि यहां जाने वाले श्रद्धालु या भक्त डेली विजिटर्स हैं और वह वहां रूकने के इरादे से नहीं जाते हैं, जिस वजह से इस रूट पर जाम की समस्या भी बढ़ जाती है।

यूपी के विधायकों की लगेगी क्लास, आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर देंगे ट्रेनिंग, एआई से लैस होगी विधानसभा

आर्यावर्त संवाददाता

कानपुर। उत्तर प्रदेश विधानसभा एक ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही है, जो इसे देश की पहली ऐसी विधानसभा बनाएगा। विधानसभा में विधायकों को आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये फैसला विधायकों के कामकाज को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी और तकनीकी रूप से बेहतर बनाने के लिए लिया गया है। विधायकों को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) कानपुर के प्रोफेसर ट्रेनिंग देंगे। विधायकों की ट्रेनिंग की क्लास अगस्त में मानसून सत्र के बीच या अंत में लगेगी। इसके लिए विशेष एआई सत्र का आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने भविष्य में विशेष एआई

सहायता इकाइयों के गठन की योजना बनाई है। ये इकाइयां विधायकों को कानूनी अनुसंधान, दस्तावेजों की जांच और नीतिगत अध्ययनों में तकनीकी सहायता प्रदान करेंगी। इसके साथ ही, विधायकों और उनके कर्मचारियों के लिए नियमित कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा, ताकि वे एआई उपकरणों का उपयोग करने में दक्ष हो सकें।

इस प्रशिक्षण में विधायकों को एआई उपकरण से बिल ड्राफ्टिंग, कानूनी समस्याओं की पहचान और अन्य राज्यों या देशों के कानूनों की तुलना में सहायक होंगे। एआई विधायकों की संपत्तियों या हितों से संबंधित टकरावों का विश्लेषण कर सकता है। सोशल मीडिया, सर्वेक्षण और याचिकाओं के जरिए एआई नागरिकों की राय को समझने में मदद करेगा।

इससे प्रस्तावित कानूनों के सामाजिक और आर्थिक प्रभावों का पूर्वानुमान लगाया जा सकेगा। पुराने दस्तावेजों, बहसों और रिपोर्टों को AI के जरिए खोज योग्य बनाया जाएगा। भाषणों और दस्तावेजों का विभिन्न भारतीय भाषाओं में त्वरित अनुवाद संभव होगा। एआई डैशबोर्ड के माध्यम से सरकारी परियोजनाओं की प्रगति और खर्च की रियल-टाइम निगरानी की जा सकेगी। IIT कानपुर के प्रोफेसर इस प्रशिक्षण में अहम भूमिका निभाएंगे। वे विधायकों को AI की तकनीकी बारीकियों और इसके व्यावहारिक उपयोगों से परिचित कराएंगे। विधानसभा सचिवालय का कहना है कि यह पहल न केवल विधायकों के कार्यों को आसान बनाएगी, बल्कि नीति निर्माण और कानून बनाने की प्रक्रिया को भी अधिक प्रभावी और डेटा-आधारित बनाएगी।

सपा सांसद हरेंद्र मलिक का एलान : इकरा हसन के समर्थन में मुजफ्फरनगर में महापंचायत, बोले– सड़क से संसद तक लड़ेंगे!

आर्यावर्त संवाददाता

मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद हरेंद्र मलिक ने सहारनपुर की घटना पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इकरा हसन के साथ जो कुछ हुआ, वह बेहद निंदनीय है और इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

उन्होंने ऐलान किया कि कांवड़ यात्रा संपन्न होने के बाद मुजफ्फरनगर में राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान पर एक बड़ी महापंचायत आयोजित की जाएगी, जिसमें इकरा हसन को न्याय दिलाने और समाज में सौहार्द कायम रखने की दिशा में रणनीति तय की जाएगी।

सांसद हरेंद्र मलिक ने कहा कि यह सिर्फ एक महिला का मामला नहीं, बल्कि संविधान, समानता और

आवाज उठाने के अधिकार का मामला है। 'यह लड़ाई सड़क से संसद तक लड़ी जाएगी।

राजनीतिक सवालों के जवाब में उन्होंने 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने का दावा किया। अपने परिवार को लेकर उन्होंने साफ कहा कि छोटे बेटे को चुनाव लड़ाने की कोई योजना नहीं है, जबकि बड़े बेटे पंकज मलिक चरथावल से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि 'शामली, मुजफ्फरनगर, चरथावल और सदर- चारों सीटें उनके लिए मुफीद हैं।

डाक्टरों की टीम ने किया अनोखा आपरेशन, बचाई जान

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुलतानपुर। जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज बनते ही डाक्टरों ने अपनी प्रतिभाओं का लोहा मनवाना शुरू कर दिया है। देखते ही देखते ऐसी कई सर्जरी हुई जो जनपद के लिए एक नये तजुर्बे से कम नही है। जिले के कुछ बाजारू व्यवसायिक निजी नर्सिंग होम ने अपने संस्थान में भर्ती मरीजों को तब तक चूसने का काम किया जब तक उसके शरीर में खून की बूंदे बची रही, और अंत में अंतिम समय समझकर उसे अंयत्र जाने के लिए संस्थान खाली करने का फ़रमान सुना दिया। आखिर में मरीज के परिजनों के पास जब विकल्प के रूप में सिर्फ मेडिकल कॉलेज बचता है, तो फिर (मरता क्या ना करता) थक-हार कर पहुंचता है, तो उसके पास सिर्फ भगवान और धरती के भगवान मात्र यही दो सहारा बचता है। ऐसा ही एक मामला बीती रात देखने को मिला। एक

निजी नर्सिंग होम से आरती मौर्य को उस समय बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, जब आरती के पेट में लगभग 3लीटर खून का थक्का जम गया, डेढ़ माह का गर्भ भी खराब हो गया, आरती मौर्य और मौत के फासले में कम अंतर देखकर व्यवसाई ने हाथ खड़े कर लिए। परिजन आरती को लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंचे, रात में ही डाक्टरों ने आरती की हालत की स्थिति को देखते हुए टीम तैयार की और शुरु हुआ आपरेशन, वरिष्ठ एनेस्थेटिक्स डॉ. निशीकांत गुप्ता, डॉ. अंजली चौधरी, ओटी टेक्निशियन इरफान, स्टाफ नर्स सुमन गौतम, नमिता यादव, वार्ड आया पिंकी यादव के अथक प्रयास से दो घंटे चला आपरेशन कामयाब रहा। मरीज के परिजनों ने डाक्टरों की टीम की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए कहाकि मेरे लिए भगवान यही है, जिनकी वजह से हम आज अपने मरीज को अपने बीच देख रहे है।

छांगुर के शहजाद से भी मिले कनेक्शन, एक करोड़ दिया गया था...पुणे में भी होगी जांच, ईडी की कार्रवाई जारी

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

बलरामपुर। अवैध धर्मांतरण के आरोप में एटीएस की ओर से गिरफ्तार किए गए जमालुद्दीन उर्फ छांगुर मामले में प्रवर्तन निदेशालय 14 ठिकानों पर तलाशी ले रहा है, जिनमें से 12 उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के उतरौला में और दो मुंबई में हैं। तलाशी आज सुबह 5 बजे शुरू हुई। ईडी ने उसके कांप्लेक्स की पड़ताल के साथ ही मधुपुर स्थित उसके आवास को भी खंगालना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही ईडी छांगुर के करीबियों के घरों पर पहुंच कर छानबीन कर रही है। छांगुर को मधपुर में जमीन बेचने वाले पूर्व प्रधान जुम्मन के घर भी ईडी ने दस्तक दे दी। वहीं, सुबह से शहर के अन्य ठिकानों पर ईडी जांच कर रही है।

प्रवर्तन निदेशालय की टीम उतरौला के 12 ठिकानों के साथ ही

मुंबई में भी छानबीन कर रही है। मुंबई के शहजाद शेख के घर ईडी पहुंच गई है। इसके अलावा एक और ठिकाने की पड़ताल कर रही है। पुणे में भी जांच की तैयारी है। सूत्रों की मानें तो शहजाद के खाते में एक करोड़ जमा हुए थे। ईडी छांगुर की ओर से रुपए के बंटवारे का तार जोड़ने में जुटी है।

उतरौला में एसटीएफ का छापा, छांगुर के भतीजे को उठाया पूछताछ कर छोड़ा

इससे पहले, उतरौला में बुधवार की देर रात एसटीएफ की टीम पहुंची थी। रात करीब 11 बजे उतरौला बस अड्डा रोड पर टीम पहुंची। वहां एक बैंक के सामने खड़ी बाइक पर बैठे एक युवक से एसटीएफ ने पूछताछ की। इसके बाद उसे बैठा लिया। बाद में पता चला एसटीएफ की टीम ने छांगुर के भतीजे सोहराब को हिरासत में लिया है। इस पर आजमगढ़ में धर्मांतरण कराने का आरोप है। हालांकि, पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया है। जानकारी के अनुसार, अवैध धर्मांतरण के आरोपी छांगुर के ठिकानों की पड़ताल बृहस्पतिवार की सुबह से ही शुरू हो गई। एटीएस के साथ ही ईडी की टीम ने भी छानबीन तेज कर दी है। उतरौला पहुंची टीम ने छांगुर से जुड़े करीब 12 ठिकानों की पड़ताल की। उतरौला में बने छांगुर के प्रतिष्ठान का ताला खुलवा कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि छांगुर के दूसरे जिलों और प्रदेशों में ठिकानों की छानबीन भी हो रही है। ईडी छांगुर मामले में मनी लांड्रिंग के साथ ही विदेशी फंड की जांच कर रही है। उतरौला में सुबह से ही टीम पड़ताल में जुटी है।

कांप्लेक्स के साथ घर भी तलाश रही ईडी

जमालुद्दीन उर्फ छांगुर के संपत्तियों की पड़ताल ईडी ने तेज कर दी है। उसके कांप्लेक्स की पड़ताल के साथ ही मधुपुर स्थित उसके आवास को भी ईडी ने खंगालना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही ईडी छांगुर के करीबियों के घरों पर पहुंच कर छानबीन कर रही है। छांगुर मधपुर में जमीन बेचने वाले पूर्व प्रधान जुम्मन के घर ईडी ने दस्तक दी। वहीं, सुबह से शहर के अन्य ठिकानों पर ईडी जांच कर रही है।

स्कूल बंद करने के विरोध में मोस्ट का जोरदार प्रदर्शन

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। मोस्ट कल्याण संस्थान, उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में प्रदेश सरकार द्वारा विद्यालयों को बन्द किये जाने के आदेश का विरोध करते हुए मोस्ट जिला संयोजक राकेश कुमार निषाद के नेतृत्व में शिक्षा बचाओदृस्कूल बचाओ अभियान के तहत जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को सम्बोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। ज्ञापन में लिखा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21ए अंतर्गत 06 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है, यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि कोई भी बच्चा आर्थिक कारणों से शिक्षा से वंचित न रहे और राज्य की जिम्मेदारी है कि वह कानून बनाकर सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराए। अनु. 41 द्वारा राज्य को शिक्षा प्रदान करने के निर्देश के साथ-साथ प्रत्येक माता-पिता या संरक्षक को अपने 06 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना 11वां मौलिक कर्तव्य घोषित किया गया है। किंतु 16 जून, 2025 को अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उत्तर प्रदेश के समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति को प्राथमिक विद्यालयों को समीप के विद्यालयों से युग्मन का (विद्यालयों की संख्या कम करने का) संविधान विरोधी/मौलिक अधिकार विरोधी आदेश जारी किया गया है जिसका प्रदेश में व्यापक स्तर पर विरोध भी किया जा रहा है। मोस्ट ने आरोप लगाया है कि उक्त संविधान विरोधी/मूल अधिकार विरोधी आदेश का हवाला देकर जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/खण्ड शिक्षा अधिकारियों द्वारा स्कूल को बंद करने का संविधान विरोधी आदेश जारी कर स्कूल स्टाफ को डरा-धमकाकर जबरन सहमति ली जा रही है। उक्त संविधान विरोधी कृत्य से ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ने वाले बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के अवसर से वंचित होने की संभावना है।

सपेरों का सुप्रीम कोर्ट : लोहे की गर्म रॉड और सात कदम...न्याय का अनूठा तरीका, पूरे देश में होता है लागू

आर्यावर्त संवाददाता

मैनपुरी। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की किशनी तहसील में स्थित नगला बील गांव में सपेरा समुदाय का सुप्रीम कोर्ट हैं। यह गांव आम लोगों के लिए भले ही गुमनाम हो, लेकिन पूरे देश का सपेरा समुदाय इसे किसी पवित्र तीर्थ से कम नहीं मानता। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और वकील कोई कानूनी डिग्रीधारक नहीं हैं। मगर, सामान्य शिक्षित इन लोगों का फैसला पूरे देश के सपेरा समुदाय के लिए मान्य होता है।

करीब ढाई हजार की आबादी वाला यह पूरा गांव सपेरा समुदाय का ही है। यहीं पर उनका सपेरा सजातीय सर्वोच्च न्यायालय नगला बील स्थापित है, जिसे सपेरा समाज में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का दर्जा प्राप्त है। इसके मुख्य न्यायकर्ता जोरानाथ हैं, जिनको हाल में चुना गया है। इनसे पहले मलूकनाथ इस पद पर थे, उनका देहांत हो गया।

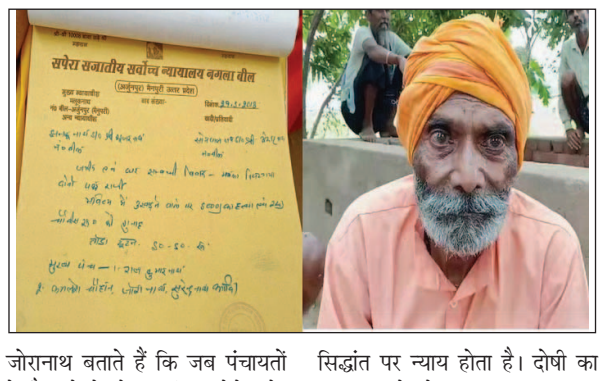

जोरानाथ बताते हैं कि जब पंचायतों के फैसलों से लोग असंतुष्ट होने लगे, तब इस 'सुप्रीम कोर्ट' की नींव रखी गई ताकि उनकी पुरानी न्यायिक परंपरा बनी रहे।

सुनवाई का अनोखा तरीका और कड़े फैसले

इस अदालत में मारपीट, लड़की भगाने, चोरी व अन्य गंभीर मामलों की सुनवाई होती है। यहां सबूतों पर नहीं, बल्कि 'सांच को आंच नहीं' के सिद्धांत पर न्याय होता है। दोषी का पता लगाने के लिए एक अनूठा अग्नि-परीक्षण भी होता है। आरोपी को पीपल के सात पत्तों पर रखी गर्म लोहे की मोटी रॉड हाथ में लेकर सात कदम चलना पड़ता है। अगर उसके हाथ जल जाते हैं, तो उसे दोषी मान लिया जाता है।

दोषी पाए जाने पर आर्थिक जुर्माने से लेकर समाज और गांव से बहिष्कृत करने तक की कड़ी सजा सुनाई जाती है। सबसे खास बात, यहां फैसला होने के बाद कोई अपील या अर्जी नहीं सुनी जाती - एक बार जो फैसला हो गया, सो हो गया। जोरानाथ कहते हैं कि वह आज भी अपनी प्राचीन परंपराओं और मान्यताओं के आधार पर सामाजिक न्याय बनाए रखते हैं और उनका रुतबा सपेरा समुदाय में किसी भी औपचारिक न्यायालय से कम नहीं है।

सपेरा समाज का हाईकोर्ट भी

सपेरा समुदाय के अपने हाईकोर्ट भी हैं। बदायूं जिले के हरपालपुर गांव में उनका मुख्य हाईकोर्ट है। इसके अलावा, कानपुर के नगला बरी, आगरा के मनियां, औरैया के पिपरी और मथुरा के छाता तहसील के बसई खुर्द गांवों में इसकी खंडपीठें हैं। जब इन निचली अदालतों के फैसलों से कोई संतुष्ट नहीं होता, तभी वह नगला बील के 'सुप्रीम कोर्ट' की शरण लेता है।

फर्जी बैनामे प्रकरण में डीएम से मिले पीड़ित व्यापारी

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश मंत्री हिमांशु मालवीय के नेतृत्व में नगर कोतवाली थाना क्षेत्र के लखनऊ नाका स्थित उदासीन संगत आश्रम गुरुद्वारा की बेशकीमती करोड़ों की संपत्ति के फर्जी बैनामे के प्रकरण पर वहां पर किराए पर व्यापार और निवास करने वाले व्यापारियों का समूह भाजपा महिला मोर्चा सुल्तानपुर की निवर्तमान जिला मंत्री मंजू सागर कसौधन के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचा। डीएम को संबोधित शिकायती पत्र में समाजवादी पार्टी सुल्तानपुर के नगर अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार अग्रहरि उर्फ राजू चौधरी तथा संतोष कुमार चौधरी व लोकनाथ अग्रहरि पर उदासीन संगत आश्रम गुरुद्वारे की संपत्ति जिसमें कई मकान व दुकान बने हुए हैं का फर्जी तरीके से बैनामा करके विक्रय करने का आरोप लगा है। हिमांशु मालवीय ने बताया कि उक्त गुरुद्वारा 275 वर्ष पुराना निर्मित है जो यहां के शिलालेखों में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। मंजू सागर कसौधन ने बताया कि पिछले 6 महीने के भीतर 9 से 10 फर्जी बैनामे हुए है, सम्पत्ति के दो मकानों का जिसमें दुकान भी शामिल है का विक्रय किया जा चुका है। पहला नगर कोतवाली थाना क्षेत्र के लखनऊ नाका रेलवे क्रॉसिंग के सामने स्थित खालसा लाउडस्पीकर सेंटर के मालिक सरदार जगदीप सिंह उर्फ राजू निवासी कृष्णानगर खैराबाद सुल्तानपुर और दूसरा दीपा शुक्ला पत्नी मनोज शुक्ला निवासी पुरानी हनुमान गढ़ी लखनऊ नाका सुल्तानपुर को किया गया है। हरजीत कौर जो गुरुद्वारे/मंदिर के अंतर्गत बने आवासीय परिसर में किराए पर निवास करती है उन्होंने बताया कि गुरुद्वारे/मंदिर की कुल संपति की कीमत लगभग 20 से 25 करोड़ की है। मनप्रीत सिंह ने कहा कि यह प्रकरण हिंदू/सिख आस्था और जनहित से जुड़ा हुआ है इसलिए उक्त प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच आवश्यक है। चुकी कोई बैनामे दानपात्र विलेख द्वारा पत्नियों तथा भाई के नाम पर किए गए है।

भाजपा विधायक के 'चाचा' की बीच सड़क पिटाई... नगर निगम कर्मियों ने डंडे से पीटा; घटना सीसीटीवी में कैद

आर्यावर्त संवाददाता

आगरा। आगरा के खेरिया मोड़ (जगनेर रोड) पर बुधवार दोपहर भाजपा विधायक भगवान सिंह कुशवाहा के चाचा की मिठाई की दुकान में प्लास्टिक के गिलास मिले। एक हजार रुपये का चालान काटने पर हुए विवाद में नगर निगमकर्मियों ने दुकानदार को डंडे से पीटा।

दुकानदार को बचाने आए भाई और पत्नी को भी पीटने का आरोप है। दोनों पक्षों ने पुलिस चौकी पर भी हंगामा किया। दोनों पक्ष के 3-3 लोगों का मेडिकल पुलिस ने कराया है। घटना का वीडियो भी वायरल हुआ है। जगनेर रोड पर जगदीश कुशवाहा की नत्थी मिष्ठान भंडार नाम से दुकान है। वह खेरागढ़ से विधायक भगवान सिंह कुशवाहा के रिश्ते के चाचा हैं। दुकान के बगल में शराब का ठेका भी है। दुकानदार ने बताया कि सुबह 10 बजे

दुकान खोली थी।

दोपहर में 1 बजे नगर निगम के सेनेटरी फूड इंस्पेक्टर (एसएफआई) प्रदीप गौतम आए। दुकान में रखे प्लास्टिक के 4 गिलास और पॉलिथीन पर चालान काटने लगे। उन्होंने कहा कि 5000 का चालान होगा।

कुछ कम करने के लिए विधायक का नाम लेते ही सेनेटरी इंस्पेक्टर अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे। भाई मुकेश कुशवाहा को बुलाया। उन्होंने भी समझाया लेकिन वो नहीं माने। तीन हजार लेने के बाद एक हजार की रसीद दी। विरोध पर सील कराने की धमकी देकर चले गए। दुकानदार ने बताया कि बाद में बुलडोजर और 15-20 कर्मचारियों के साथ डंडे लेकर आए। उन्हें जमीन पर गिराकर पीटा। बचाने आए भाई नीरज और पत्नी मंजू की भी पिटाई की। डर से दूसरे दुकानदार

> निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को मानकों एवं नियमों के आधार पर कार्रवाई करनी चाहिए। मिठाई दुकानदार के साथ हुई घटना अधिकारियों की तानाशाही को दर्शाती है। बसपा व्यापारियों के साथ है। निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी कार्यशैली बदलनी होगी।
>
> सुनील शर्मा, पार्षद, बसपा

बचाने नहीं आए।

उन्होंने पुलिस चौकी में तहरीर दी। बाद में कर्मचारियों ने बुलडोजर से काउंटर, दुकान का शटर तोड़ दिया। उधर, एसएफआई प्रदीप गौतम का कहना है कि दुकानों पर कार्रवाई की जा रही थी। नत्थी मिष्ठान भंडार के दुकानदार चालान का विरोध करने लगे। अभद्रता की।

शमन शुल्क देने से मना किया और लोहे की सरिया से हमला बोला दिया। सफाई मित्र भोला और मधुसूदन के सिर और कंधे पर चोट लगी है। पथराव भी किया। बाद में अतिक्रमण की कार्रवाई की गई।

मारपीट के बाद दोनों पक्ष सराय ख्वाजा पुलिस चौकी पहुंचे। करीब एक घंटे तक हंगामा हुआ। बाद में 6 लोगों को मेडिकल के लिए भेजा गया। एसीपी लोहामंडी मयंक तिवारी ने बताया कि जगदीश, नीरज और मंजू कुशवाहा, वहीं निगम कर्मचारी प्रदीप गौतम, भोला और मधुसूदन का मेडिकल कराया है। तहरीर मिलने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

चालान के बाद दुकान पर क्यों चलाया बुलडोजर?

दुकानदार जगदीश कुशवाहा का आरोप है कि उन्होंने चालान की कार्रवाई का विरोध किया। इस पर मारपीट की गई। उनकी दुकान नाले के ऊपर नहीं है। इसके बावजूद उनकी दुकान पर बुलडोजर चलवाया गया। काउंटर तोड़ दिया। शटर भी तहस-नहस कर डाला। वह और विधायक के भाई हाथ जोड़कर खड़े रहे, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी। दुकानदार ने कहा कि अगर, किसी तरह की कार्रवाई करनी थी तो पुलिस को लेकर आना चाहिए था। निगमकर्मियों के पीटने पर वह सड़क पर गिर गए।

सीएम से करेंगे शिकायत

विधायक भगवान सिंह कुशवाहा ने बताया कि रिश्तेदार की दुकान पर निगमकर्मी गए थे। गलत तरीके से चालान की कार्रवाई की। अभद्रता की गई। वो लखनऊ में हैं। इस मामले को मुख्यमंत्री के समक्ष लेकर जाएंगे। आगरा आकर नगरायुक्त और जिलाधिकारी से वार्ता करेंगे। कार्रवाई बिना मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में की गई।

अपर नगर आयुक्त करेंगे जांच

खेरिया मोड़ पर दुकानदार और नगर निगमकर्मियों के बीच हुए विवाद की जांच के लिए नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने अपर नगर आयुक्त शिशिर कुमार को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। अतिक्रमण और पॉलिथीन मुद्दे पर विवाद हुआ था।

छाती पर पैर रखकर पीटने का वीडियो

पुलिस और निगम अधिकारियों को मारपीट के वीडियो और सीसीटीवी फुटेज मिले हैं। एक वीडियो एसएफआई से बातचीत का है। दुकानदार 1000 की जगह पर 500 रुपये का चालान काटने की कह रहे हैं। इसके सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी हैं। एक और वीडियो पिटाई का है। जिसमें हाथों में डंडे लिए कर्मचारी दुकानदार को पीट रहे हैं। इनमें एक कर्मचारी दुकानदार की छाती पर पैर भी रखे हुए है।

दोनों पक्षों में समझौते के प्रयास

अजीत नगर बाजार कमेटी के अध्यक्ष राजेश यादव ने बताया कि बाजार में शराब के ठेके के पास गिलास बिक्री पर विवाद हुआ था। नगर निगम की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। मामले में खेरागढ़ के विधायक से वार्ता की गई है। वह आगरा से बाहर हैं। दोनों पक्षों में समझौते के प्रयास कराए जा रहे हैं।

500 से अधिक छात्र संख्या वाले परिषदीय स्कूल बनेंगे 'आदर्श स्कूल', दो हजार करोड़ मंजूर

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संपूर्ण कायाकल्प के लिए दो हजार करोड़ का बजट मंजूर किया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए यह योजना बेसिक शिक्षा विभाग की अब तक की सबसे बड़ी निवेश योजना मानी जा रही है।

इसको लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि हम शिक्षा को सिर्फ विद्यालय उपस्थिति तक सीमित नहीं रखना चाहते। बल्कि, उसे संरचनात्मक, तकनीकी और बौद्धिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि यूपी को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में स्थापित करें। हर बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचे। इसके लिए नवाचार और पारदर्शिता के साथ कार्य कर रहे हैं।

मंत्री ने कहा कि इसके तहत परिषदीय विद्यालयों में भवन निर्माण, संसाधन सुदृढ़ीकरण, पेयजल, शौचालय, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, एमडीएम शेड, रैंप और चारदीवारी जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। सरकार के विजन प्राथमिक शिक्षा, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के अनुरूप ही इस कार्य योजना को गति दी जाएगी। प्रदेश में शिक्षा में सुधार केवल आंकड़ों में नहीं, बल्कि बच्चों के सीखने की गुणवत्ता और विद्यालयी जीवन के अनुभव पर भी दिखेगा।

इन सुविधाओं से लैस होंगे विद्यालय

मंत्री संदीप सिंह ने आगे बताया कि अक्सर देखा जाता है कि कम नामांकन वाले विद्यालयों में संसाधनों के बावजूद अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते। जबकि, अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालयों में संसाधनों की सीमितता के बावजूद बेहतर उपयोग होता है। अब 500 या अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालयों को 'आदर्श विद्यालय' के रूप में उच्चीकृत किया जाएगा। इन विद्यालयों को स्मार्ट क्लास, लाइब्रेरी रूम, मल्टीपरपज हॉल, क्लब रूम, कंप्यूटर और ICT लैब, 'लर्निंग बाय डुइंग' स्पेस और एमडीएम शेड सहित अन्य सुविधाएं मिलेंगी।

पहले से अधिक प्रभावी होंगी सह-शिक्षण की व्यवस्थाएं

महानिदेशक स्कूल, कंचन वर्मा ने कहा कि इस रणनीति से प्रदेश के स्कूलों में छात्र नामांकन में वृद्धि, पियर लर्निंग का विस्तार, सक्रिय सहभागिता और अनुभवात्मक अधिगम को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही शिक्षकों के लिए भी समय सारणी आधारित कक्षा आवंटन, कार्य विभाजन और सह-शिक्षण की व्यवस्थाएं और अधिक प्रभावी होंगी।

सुशान्त गोल्फ सिटी इलाके के ग्रीन सिटी मोड़ पर गिरा पेड़

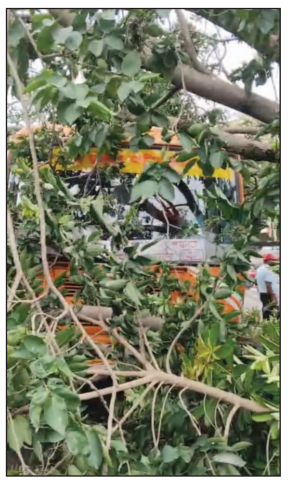

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में गुरुवार को ग्रीन सिटी मोड़ पर अचानक एक पेड़ गिर गया। इस घटना के कारण अर्जुनगंज से लेकर सरसवां तक का मार्ग बाधित हो गया। सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। यातायात व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हुई। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई और कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ।पेड़ के नीचे एक बाइक भी दबकर छती ग्रस्त हो गई। पेड़ गिरने के बाद सड़क के दूसरी और से यातायात चल रहा हैं। इस दौरान वाहनों की लंबी कतार लग गई। वाहन धीरे धीरे निकल रहे हैं।

प्लासियो मॉल स्थित बार से निकले युवक पर दबंगों ने किया जानलेवा मामला

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। सुशांत गोल्फ सिटी कोतवाली क्षेत्र के शहीद पथ के किनारे स्थित प्लासियो मॉल के बार से निकले युवक पर गेट के बाहर एस यू वी पर मौजूद आधा दर्जन से अधिक लोगों ने अचानक हमला बोल दिया,पीड़ित जब तक कुछ समझ पाता, वहां मौजूद बाउंसरों से डंडे लेकर सिर पर कई वार कर दिए, जिससे पीड़ित लहूलुहान होकर गिर गया। सूचना पर पहुंची पुलिस पीड़ित और आरोपियों को कोतवाली ले गई।

अनुज सिंह, त्रिवेणीनगर, सीतापुर रोड लखनऊ में रहते हैं। उन्होंने बताया कि बीती 13-14 जुलाई की देर रात करीब 2 बजे प्लासियो मॉल स्थित ₹टानिक बार, से निकला था। गेट पर मौजूद लोगों ने अचानक जानलेवा हमला कर दिया। माल के गेट पर खड़ी XUV कार में करीब 6-से 7 लोग सवार थे। वह बार शीशा तोड़ने की बात कर रहे थे।जब कि उनकी गाड़ी का शीशा अन्य लोगों ने तोड़ा था। बार बार कहने पर भी नहीं माने ।

अनुज सिंह ने बताया कि तीन लोगों ने वहां खड़े बाउंसरों के डंडे छीनकर जान से मारने की नियत से कई बार डंडे से वार किया।

पीड़ित ने बताया कि वहां उपस्थित अन्य लोगों ने किसी तरह से उसे बचाया, मौके पर पहुंची पुलिस पीड़ित अनुज सिंह व 2 आरोपियों को कोतवाली सुशांत गोल्फ सिटी ले गये जहां विधिक कार्रवाई की गई।

बिजली की कटौती से मिलर परेशान

लखनऊ। गोसाईगंज क्षेत्र के विद्युत उपखंड अमेठी से पोषित गंगागंज की विद्युत कटौती से उधर के उपभोक्ता काफी परेशान है। रविंद्र राइस मिल गंगागंज के प्रोपराइटर रविंद्र नाथ का कहना है कि लगातार बिजली की कटौती से हम लोगों का व्यवसाय प्रभावित हो रहा है।उनका कहना है कि जब से अमेठी फीडर बनाया गया है तब से लगातार विद्युत कटौती की जा रही है।विद्युत आपूर्ति चालू भी होती है तो आपूर्ति इतनी बार बाधित की जाती है कि मशीनें चल ही नहीं पाती।जिससे आए दिन हम लोगों के यहां दर्जनों मजदूर दिन भर बैठे रहते हैं जिसके कारण मिल बंद रहता है।उनका आरोप है कि विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर उसका कारण जानने या अपनी कोई समस्या बताने के लिए जब एसडीओ या जे ई सहित अन्य अधिकारियों को फोन करो तो वह लोग फोन ही नहीं उठाते है।जबकि हम लोग लाखों में विद्युत बिल का भुगतान करते हैं ।

लखनऊ बना देश का तीसरा सबसे स्वच्छ शहर, राष्ट्रपति ने विज्ञान भवन में किया सम्मानित

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ने स्वच्छता के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के अंतर्गत विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित भव्य समारोह में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने लखनऊ नगर निगम को देश के तीसरे सबसे स्वच्छ शहर का 'प्रेसीडेंशियल अवार्ड' देकर सम्मानित किया। यह उपलब्धि न केवल लखनऊ के नागरिकों की जागरूकता और समर्पण की पहचान है, बल्कि पूरे प्रदेश के लिए गौरव का विषय भी बनी है।इस वर्ष उत्तर प्रदेश ने स्वच्छता के विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देश में अपनी उपस्थिति मजबूत की है। देश के शीर्ष 3 स्वच्छतम शहरों में लखनऊ पहली बार शामिल हुआ है, जबकि पहले यह स्थान अन्य राज्यों के शहरों के कब्जे में था। इसके साथ ही शीर्ष 10 और 25 स्वच्छतम शहरों में भी प्रदेश के सात शहरों – लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी और मेरठ – ने स्थान बनाया है। यह साफ-सुथरे और स्वस्थ नगरीय जीवन की दिशा में प्रदेश की बढ़ती प्रगति का प्रमाण है।नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री ए.के. शर्मा ने इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सम्मान प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन की दूरदर्शिता और मुख्यमंत्री की प्रतिबद्धता का परिणाम है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगरीय स्वच्छता को एक जन आंदोलन के रूप में विकसित किया है और हर शहर को साफ-सुथरा बनाने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश और संसाधन प्रदान किए हैं।इस उपलब्धि के पीछे नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा का कुशल नेतृत्व, सतत निरीक्षण और त्वरित निर्णय क्षमता अहम रही है। पिछले वर्ष जहां लखनऊ की रैंकिंग 44वीं थी, वहीं इस बार यह सीधे शीर्ष तीन में आ गया है। लखनऊ नगर निगम द्वारा अपनाई गई डिजिटल निगरानी प्रणाली, कचरा पृथक्करण के प्रयास और शिवरी वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट पर प्रभावी निस्तारण को विशेषज्ञों और राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय मंचों पर सराहा गया है।नगर निगम की पहल के तहत कूड़ा प्रबंधन में वैज्ञानिक तरीके से कचरे का पृथक्करण किया जा रहा है तथा शिवरी संयंत्र पर लगभग 20 लाख टन कूड़े का सफल निस्तारण

साइबर ठगों ने युवक से ठगे 92हजार, मुकदमा दर्ज

लखनऊ। सुशांत गोल्फ सिटी कोतवाली क्षेत्र के अवध बिहार योजना में रहने वाले एक युवक से साइबर ठगों ने खुद को फिलपकर्ट कस्टमर केयर का कर्मचारी बताकर सामान के रिफंड को लेकर उसके क्रेडिट कार्ड से चार बार में 92 हजार रुपए ठग लिए,ठगी की जानकारी होने पर पीड़ित ने साइबर सेल,बैंक को सूचित कर सुशांत गोल्फ सिटी कोतवाली पुलिस को तहरीर दी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। अतुल कुमार त्रिपाठी, मंदाकिनी एन्क्लेव, अवध विहार योजना,, सुशांत गोल्फ सिटी,लखनऊ में रहते हैं। अतुल कुमार के मुताबिक बीती 16 जून को शाम करीब 7 बजे फिलपकर्ट कस्टमर केयर का कर्मचारी बताकर खरीदे गए सामान के रिफंड को लेकर फोन किया,और बातों में उलझाकर बैंक आफ इंडिया के क्रेडिट कार्ड संख्या 5420343025572095 से धोखाधड़ी करके पांच बार में 18999/. 26921, 12299/- 25000/- 9000/- कुल 92, हजार 221 रुपए ठग लिए।

फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर 85 लाख की साइबर ठगी करने वाला आरोपी दोष सिद्ध

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। साइबर क्राइम थाना लखनऊ और अभियोजन शाखा की संयुक्त पैरवी के चलते फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर ₹डिजिटल गिरफ्तारी₹ के नाम पर 85 लाख रुपये की साइबर ठगी करने वाले आरोपी देवाशीष राय को विशेष न्यायालय, लखनऊ ने दोषी करार देते हुए रिकार्ड समय में सजा सुनाई है। आरोपी को अलग-अलग धाराओं में कुल 7 वर्ष के सश्रम कारावास और भारी अर्थदंड से दंडित किया गया है। यह उत्तर प्रदेश में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर हुई साइबर ठगी में पहली दोषसिद्धि और सजा है।घटना 1 मई 2024 की है जब डॉक्टर सौम्या गुप्ता को उनके ड्यूटी के दौरान एक अज्ञात कॉल प्राप्त हुई। कॉल करने वाले ने स्वयं को कस्टम अधिकारी बताते हुए दावा किया कि उनके नाम से एक कार्गो बुक किया गया है जिसमें जाली पासपोर्ट, एटीएम कार्ड और 140 ग्राम MDM मिला है। इसके बाद कॉल को एक अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर कर दिया गया, जिसने खुद को सीबीआई अधिकारी बताया। उसने वादिनी को धमकाते हुए "डिजिटल गिरफ्तारी" का डर दिखाकर 10 दिनों तक 85 लाख रुपये की ठगी की।इस संबंध में थाना साइबर क्राइम लखनऊ में आईपीसी की धारा 419, 420, 467, 468, 471 तथा आईटी एक्ट की धारा 66डी के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई। जांच के क्रम में पुलिस आयुक्त लखनऊ के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक बृजेश कुमार यादव की टीम ने तकनीकी संसाधनों, सर्विलांस और साक्ष्य विश्लेषण की मदद से आरोपी की पहचान की। आरोपी देवाशीष राय ने फर्जी फर्म के नाम से बैंक खाता खुलवाकर और अलग-अलग सिम लेकर यह अपराध किया था। टीम ने आरोपी को 5 मई 2024 को गोमतीनगर विस्तार स्थित मंदाकिनी अपार्टमेंट से गिरफ्तार किया और 2 अगस्त 2024 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया गया।शासन स्तर पर चलाए जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अंतर्गत अभियुक्त की जमानत का विरोध करते हुए जिला कारागार में निरुद्ध रखा गया और त्वरित सुनवाई के लिए सघन पैरवी की गई। साक्ष्यों की पुष्टि, बरामदगी और गवाहों के बयान के आधार पर माननीय विशेष CJM कस्टम न्यायालय, लखनऊ ने आरोपी को दोषी करार देते हुए अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई। धारा 419 में 2 वर्ष का कारावास और 2 हजार रुपये का जुर्माना, धारा 420 में 5 वर्ष का कारावास और 3 हजार रुपये का जुर्माना, धारा 467 में 7 वर्ष का कारावास और 5 हजार रुपये का जुर्माना, धारा 468 में 5 वर्ष का कारावास और 3 हजार रुपये का जुर्माना, धारा 471 में 7 वर्ष का कारावास और 5 हजार रुपये का जुर्माना तथा आईटी एक्ट की धारा 66डी के तहत 2 वर्ष का कारावास और 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।

कार से युवक का मोबाइल फोन चोरी, मुकदमा दर्ज

लखनऊ। सुशांत गोल्फ सिटी कोतवाली क्षेत्र के पार्थ आयंत के,एल आई जी पार्किंग में खड़ी कार का दरवाजा खोल कर चोरों ने मोबाइल चोरी कर लिया,जानकारी होने पर पीड़ित ने सुशांत गोल्फ सिटी कोतवाली पुलिस को तहरीर दी, पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल कर रही है।

रोहित चौहान, पार्थ आयंत एल आई जी , शहीद पथ, शान-ए-अवध कॉम्प्लेक्स के पास, सेक्टर 7 अहमामऊ, लखनऊ में रहते हैं। पीड़ित ने बताया कि बीती 10 जुलाई की रात करीब 11:30 बजे अपनी कार यूपी 80HJ9668) पार्थ आयंत (एल आई जी) की पार्किंग क्षेत्र में खड़ी की थी।लगभग 15 मिनट बाद जब वापस लौटा, तो देखा कि कार का दरवाज़ा खुला था, और मोबाइल फोन (सैमसंग मॉडलः एस 23 अल्ट्रा चोरी हो गया है, उन्होंने बताया कि पार्किंग में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है। पुलिस तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल कर रही है।

पुलिस ने फर्जी SOG बनकर ठगी करने वाले अंतरजनपदीय गिरोह का किया भंडाफोड़

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। राजधानी के गोमतीनगर थाना क्षेत्र में पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ की पूर्वी जोन क्राइम टीम और थाना गोमतीनगर पुलिस ने मिलकर एक ऐसे अंतरजनपदीय ठग गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो खुद को पुलिस की क्राइम ब्रांच यानी SOG का अधिकारी बताकर लोगों को निवेश के नाम पर धोखा दे रहा था। इस गिरोह के चार सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में नकली नोट, नगद राशि, फर्जी पुलिस पहचान पत्र और एक अवैध तमंचा बरामद किया गया है।यह कार्रवाई उस वक्त सामने आई जब 16 जुलाई को राजकुमार यादव नामक व्यक्ति ने थाना गोमतीनगर में तहरीर दी कि कुछ लोगों ने खुद को पुलिस अधिकारी बताकर उसे पैसे डबल करने का झांसा दिया और फिर

उसके साथ लाखों रुपये की धोखाधड़ी की। उन्होंने बताया कि यह ठग पुलिस क्राइम ब्रांच से होने का दावा कर दबाव बनाते थे और निवेश के नाम पर रुपये हड़प लेते थे। इस प्रकरण पर गोमतीनगर थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(2)/318(4) बीएनएस के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच उपनिरीक्षक आनंद कुमार यादव को सौंपी गई।तत्पश्चात, पुलिस ने एक सक्रिय टीम बनाकर मुखबिरों की सूचना के आधार पर 17 जुलाई की रात विनीत खंड स्थित आईआईएलएम रोड के पास से चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्तों में विशाल कुमार (निवासी लखनऊ), रामबहादुर (निवासी संतकबीर नगर), रामप्रसाद (निवासी महाराजगंज) और अंजनी कुमार (निवासी समस्तीपुर, बिहार) शामिल हैं। ये सभी अलग-अलग जिलों से आकर लखनऊ में सक्रिय रूप से फर्जीवाड़े को अंजाम दे रहे थे।गिरफ्तार आरोपियों के पास से 500-500 रुपये के 60 असली नोट (₹30,000), 'CHILDERN BANK' लिखे नकली नोटों की 30 गड्डियां और 8 गड्डियां जिनमें ऊपर असली नोट लगाकर नीचे फर्जी नोट लगाए गए थे, बरामद की गईं। साथ ही, उनके पास से एक अवैध देशी तमंचा 315 बोर और एक जिंदा कारतूस भी मिला। इतना ही नहीं, आरोपी खुद को पुलिस अधिकारी दिखाने के लिए फर्जी पहचान पत्र भी बनाए हुए थे, जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया है।चारों आरोपियों की तलाशी के दौरान नकद रुपए अलग-अलग हिस्सों से बरामद हुए। विशाल

एचपीवी से जुड़े कैंसर को हराने के लिए लखनऊ में हुआ 'कॉनकर एचपीवी एंड कैंसर कॉन्क्लेव 2025', विशेषज्ञों ने दी टीकाकरण और जागरूकता पर जोर

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ।एचपीवी (ह्यूमन पेपिलोमा वायरस) से जुड़ी बीमारियों, खासतौर से सर्वाइकल कैंसर की गंभीर चुनौती का समाधान खोजने के उद्देश्य से लखनऊ में 'कॉनकर एचपीवी एंड कैंसर कॉन्क्लेव 2025' का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य एचपीवी से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति समाज को जागरूक करना और इससे बचाव के उपायों पर चिकित्सकीय व सामाजिक विमर्श को बढ़ावा देना था। यह कॉन्क्लेव सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव का हिस्सा है।कार्यक्रम में देश के अग्रणी चिकित्सा विशेषज्ञों ने एचपीवी वायरस के कारण होने वाले विभिन्न कैंसरों, खासकर महिलाओं में होने वाले सर्वाइकल कैंसर, वलवा, वैजाइना और पुरुषों में गुदा, लिंग एवं ओरोफेरिंक्स कैंसर को लेकर विस्तार से जानकारी दी। डॉक्टरों ने बताया

कि एचपीवी संक्रमण 15 से 25 वर्ष की आयु के बीच सबसे अधिक फैलता है और इसके प्रभाव से बचने के लिए समय रहते पहचान और वैक्सीनेशन अत्यंत आवश्यक है।पैनल में शामिल डॉ. अभिषेक बंसल, डॉ. संगीता मेहरोत्रा, डॉ. सौम्या गुप्ता, डॉ. सोनिया लूथरा, डॉ. आशुतोष वर्मा जैसे विशेषज्ञों ने एचपीवी को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करते हुए बताया कि यह वायरस केवल महिलाओं के लिए ही नहीं, बल्कि पुरुषों के लिए भी घातक हो सकता है। उन्होंने कहा कि अब भारत में कम लागत वाली और प्रभावशाली एचपीवी वैक्सीन 'सर्वावैक' उपलब्ध है, जिससे बड़ी संख्या में जिंदगियों को बचाया जा सकता है।सत्र का संचालन डॉ. उत्कर्ष बंसल ने किया। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि इस वैक्सीन को किशोरों और युवाओं के लिए समय पर देना एचपीवी संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने में सबसे प्रभावी कदम है।सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पराग देशमुख ने कहा, "हमारा उद्देश्य है कि समाज के हर वर्ग—चिकित्सक, पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स, माता-पिता और शिक्षक—को इस विषय पर जागरूक बनाएं। हम रोकथाम को स्वास्थ्य नीतियों का प्राथमिक हिस्सा बनाना चाहते हैं ताकि समय रहते कार्रवाई हो और अनगिनत जिंदगियां बच सकें।"कार्यक्रम का समापन एक खुले सत्र के साथ हुआ जिसमें उपस्थित दर्शकों और विशेषज्ञों के बीच संवाद हुआ। इस दौरान 'सही समय पर निर्णय और समाज की भागीदारी से रोके जा सकने वाले कैंसर को रोकने' के उद्देश्य को दोहराया गया।गौरतलब है कि पुणे स्थित सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन उत्पादक कंपनी है, जिसने वर्षों से सस्ती और असरदार वैक्सीन उपलब्ध कराकर लाखों लोगों की जान बचाई है। भारत की पहली स्वदेशी एचपीवी वैक्सीन 'सर्वावैक' इस दिशा में उसका अहम योगदान है। यह वैक्सीन जेंडर-न्यूट्रल और क्वाड्रिवेलेंट है, जो महिला और पुरुष दोनों को दी जा सकती है।आने वाले महीनों में यह कैंपेन देश के अन्य शहरों में भी आयोजित होगा, जिससे व्यापक जनजागरूकता और ठोस समाधान की दिशा में कदम बढ़ाए जा सकें।

प्रदेश सरकार के 27,000 सरकारी स्कूल बंद करने और 27,308 शराब की दुकानें खोलने के फैसले के खिलाफ आप सांसद संजय सिंह का विरोध प्रदर्शन

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। संभल जनपद में आप यूपी प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रदेश सरकार की शिक्षा और समाज विरोधी नीतियों के खिलाफ जोरदार विरोध जताया। प्रदेश सरकार द्वारा 27,000 सरकारी स्कूल बंद करने तथा 27,308 शराब की दुकानें खोलने के फैसले के विरोध में उन्होंने आप पार्टी की स्कूल बचाओ मुहिम के तहत प्राथमिक विद्यालय मोहम्मदपुर हुमायूंपुर से लेकर प्राथमिक विद्यालय रजबपुर विकास खण्ड जोया तक बच्चों और अभिभावकों के साथ पैदल मार्च किया।संजय सिंह ने कहा कि शिक्षा का अधिकार कानून के तहत हर बच्चे का अधिकार है कि उसके नजदीक एक स्कूल हो जिसमें उसे सभी मूलभूत सुविधाएं मिलें, लेकिन योगी सरकार ने न केवल इस संवैधानिक अधिकार की उपेक्षा की है, बल्कि बच्चों को उनके स्कूलों से दूर कर अनपढ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब नेता, जज और आईएएस अधिकारी अपने बच्चों को विदेशों में शिक्षा दिला रहे हैं, तो देश के गरीब, दलित और वंचित बच्चों के स्कूल क्यों बंद किए जा रहे हैं? क्या वे अधिकारी और नेता अपने बच्चों को इतनी दूर पैदल स्कूल भेजेंगे?एक अभिभावक ने अपने कष्टों का बखान करते हुए बताया कि वे बड़ी मेहनत से अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं ताकि वे पढ़-लिखकर आगे बढ़ सकें, लेकिन स्कूलों की दूरी इतनी बढ़ा दी गई है कि अब यह संभव नहीं रह गया। संजय सिंह ने कहा कि सरकार बच्चों को शिक्षा से वंचित करने की नीति पर काम कर रही है।सांसद संजय सिंह ने प्रदेश में प्राथमिक स्तर पर लगभग 1.93 लाख शिक्षक, माध्यमिक स्तर पर 3,872 और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर 8,714 शिक्षक पद खाली होने का आंकड़ा पेश करते हुए कहा कि सरकार शिक्षक भर्ती के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। उनका कहना था कि यह सरकार गरीब, दलित और वंचित समाज के बच्चों को शिक्षा से दूर रखना चाहती है।उन्होंने कहा कि योगी सरकार का असली चेहरा अब जनता के सामने आ चुका है। स्कूलों का मर्ज होना या खस्ताहाल स्थिति में छोड़ देना इस सरकार की नियति है। आप पार्टी ने पूरे प्रदेश में 'स्कूल बचाओ आंदोलन' शुरू किया है और 'मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए' के नारे के साथ यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक हर बच्चे को शिक्षक, स्कूल और शिक्षा का अधिकार नहीं मिल जाता।संजय सिंह ने इस फैसले को संविधान और कमजोर वर्गों के अधिकारों के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि वह इस मुद्दे को संसद में भी उठाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे और सड़क पर जनता के साथ मिलकर संघर्ष करेंगे ताकि बच्चों के स्कूल बचाए जा सकें और शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित हो सके।

SCO बैठक में जयशंकर और इशाक डार के भाषणों के विश्लेषण से कई बड़ी बातें सामने आईं

चीन के तियानजिन शहर में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के भाषण ने एक बार फिर यह साफ कर दिया कि दोनों देशों के बीच भले ही मंच साझा हो, लेकिन उनके दृष्टिकोण, प्राथमिकताएं और वैश्विक भूमिका को लेकर सोच में गहरी खाई कायम है। जहां भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर का वक्तव्य एक परिपक्व, आत्मविश्वासी और वैश्विक दृष्टिकोण से परिपूर्ण था, वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार का भाषण पुरानी शिकायतों, पाकिस्तान की विक्टिम कार्ड वाली छवि और कश्मीर के घिसे-पिटे मुद्दों के इर्द-गिर्द ही सिमटा रहा।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अपने भाषण में एससीओ की प्रासंगिकता, क्षेत्रीय स्थिरता और आतंकवाद के खिलाफ साझा जिम्मेदारियों पर जोर दिया। उन्होंने न सिर्फ भारत की उभरती हुई वैश्विक भूमिका को रेखांकित किया, बल्कि इस मंच के माध्यम से पाकिस्तान सहित सभी पड़ोसी देशों को स्पष्ट संदेश भी दिया कि आतंकवाद और सीमा-पार हिंसा किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। पहलगाम आतंकवादी हमले के जवाब में भारत की कार्रवाई को उचित ठहराते हुए जयशंकर ने एससीओ को आतंकवाद और चरमपंथ से निपटने के अपने स्थापना उद्देश्य से नहीं भटकने की सलाह भी दी। साथ ही जयशंकर का फोकस भारत की 'वसुधैव कुटुंबकम' की नीति और 'आत्मनिर्भर भारत' के विजन को क्षेत्रीय सहयोग से जोड़ने पर रहा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि साझा विकास तभी संभव है जब क्षेत्र में शांति और आतंकवादमुक्त माहौल हो। ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक सहयोग, कनेक्टिविटी और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर भारत के रुख ने एक जिम्मेदार और परिपक्व वैश्विक शक्ति की छवि भी पेश की।

दूसरी ओर, पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार का भाषण कहीं न कहीं भारत के विरुद्ध पूर्व निर्धारित एजेंडे और पुराने दावों का ही विस्तार प्रतीत हुआ। इशाक डार ने अप्रत्यक्ष रूप से कश्मीर का मुद्दा उठाकर इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर घसीटने की कोशिश की, जबकि एससीओ का मापदंड है कि यह मंच द्विपक्षीय विवादों के लिए नहीं, बल्कि साझा क्षेत्रीय हितों के लिए है। डार के भाषण में पहलगाम हमले से पल्ला झाड़ने, भारत के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाने और भारत के साथ संवाद की आवश्यकता भी जताने जैसी बातें मुख्य बिंदू रहीं। इशाक डार ने कहा कि पिछले तीन महीनों में दक्षिण एशिया में ''बेहद परेशान करने वाली घटनाएं'' हुईं। इशाक डार ने कहा, ''पाकिस्तान संघर्ष-विराम और स्थिर क्षेत्रीय संतुलन कायम करने की अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग है। हालांकि, हम यह स्वीकार नहीं कर सकते कि बल का मनमाना प्रयोग सामान्य हो जाए।'' देखा जाये तो पाकिस्तान एक ओर खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश करता रहा, वहीं दूसरी ओर क्षेत्रीय स्थिरता और विकास की बातें करता रहा, जो उसकी नीति में अंतर्विरोध को ही उजागर करता है।

भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के भाषण पर गौर करेंगे तो एससीओ मंच पर दोनों देशों के दृष्टिकोण में जमीन-आसमान का फर्क दिखाई देगा। जहां भारत आर्थिक विकास, आतंकवाद के विरुद्ध एकजुटता और क्षेत्रीय स्थिरता की बात कर रहा था, वहीं पाकिस्तान अब भी कश्मीर राग और भारत-विरोधी विमर्श में उलझा हुआ दिखा। भारत वैश्विक नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है, तो पाकिस्तान अब भी अपनी पहचान और अस्तित्व की राजनीति में उलझा है। इस बैठक से स्पष्ट हो गया कि पाकिस्तान अपने पुराने एजेंडे से बाहर आने को तैयार नहीं है जबकि भारत हर वैश्विक मंच पर रचनात्मक, समाधानपरक और विकासोन्मुखी दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहा है। हम आपको यह भी बता दें कि एससीओ के शीर्ष नेताओं की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाग लेने की संभावना है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने बताया है कि 20 से अधिक देशों के नेता और 10 अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख अगले महीने शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के तियानजिन शिखर सम्मेलन एवं संबंधित कार्यक्रमों में भाग लेंगे। एससीओ तियानजिन शिखर सम्मेलन 31 अगस्त से एक सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और एससीओ सदस्य देशों के अन्य नेताओं के इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने की संभावना है। यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन में जाते हैं तो सबकी निगाहें खासतौर पर भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के भाषण पर लगी रहेंगी। बहरहाल, एससीओ जैसे मंच पर भारत और पाकिस्तान के दृष्टिकोण में दिखा अंतर महज भाषणों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दोनों देशों की व्यापक विदेश नीति और भविष्य के कूटनीतिक रास्तों का संकेतक भी है।

अमर्यादित नहीं हो सकती है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

सर्वोच्च न्यायालय ने उचित ही कहा है कि "अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल समाज में नफरत और विघटन को जन्म दे सकता है। इसलिए नागरिकों को चाहिए कि वे जिम्मेदारी से बोलें, संयम रखें और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें"।

लोकेन्द्र सिंह राजपूत

जब हम विरोध, आलोचना और असहमति के वास्तविक स्वरूप को भूलते हैं तब हमारी अभिव्यक्ति घृणा और नफरत में बदल जाती है। मौजूदा समय में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रीय विचार के संगठनों एवं कार्यकर्ताओं पर टिप्पणी का स्वर ऐसा ही दिखायी पड़ रहा है, जो अमर्यादित है। सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसी ही अमर्यादित अभिव्यक्ति के मामलों की सुनवाई के दौरान बहुत महत्वपूर्ण बातें कहीं है, जिन पर हमें गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की रीढ़ है। इस पर किसी प्रकार के बाहरी प्रतिबंध लगाना उचित नहीं होगा। लेकिन यदि इसी प्रकार अमर्यादित लिखा-पढ़ी, बयानबाजी और कार्टूनबाजी जारी रही तब समाज में वैमनस्य और सांप्रदायिक तनाव को फैलने से रोकने के लिए कुछ न कुछ युक्तियुक्त प्रबंध करने ही पड़ेंगे। सोशल मीडिया के इस दौर में किसी को भी अमर्यादित और असीमित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती है। नागरिकों को भी समझना चाहिए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की एक मर्यादा है, उसे लांघना किसी के भी हित में नहीं है। उचित होगा कि नागरिक समाज इस दिशा में गंभीरता से चिंतन करे। सर्वोच्च न्यायालय ने उचित ही कहा है कि "अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल समाज में नफरत और विघटन को जन्म दे सकता है। इसलिए नागरिकों को चाहिए कि वे जिम्मेदारी से बोलें, संयम रखें और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें"।

हमारे यहाँ तो महापुरुषों ने भी कहा है कि जो व्यवहार हम अपने लिए अपेक्षित करते हैं, वही व्यवहार हमें सामने वाले के साथ करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ के सामने आया वजाहत खान का मामला ऐसा ही है, जिसमें हिन्दू देवी पर तो आपत्तिजनक पोस्ट कर रहा है लेकिन इस्लाम के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों के विरुद्ध शिकायत दर्ज करा है। जब पलटकर किसी ने हिन्दू धर्म का अपमान करने के आरोप में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी, तो वह न्यायालय में पहुँच गया है। याद हो कि सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनौली ने ऑपरेशन सिंदूर के समय भावावेश में आकर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। हालांकि जब उसे अपनी गलती का अहसास हुआ तो उसने बिना शर्त माफी भी माँग ली और अपना वह वीडियो भी हटा लिया था। लेकिन इसके बावजूद वजाहत खान ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी थी। हालांकि ऐसा करते समय वजाहत खान ने अपने गिरेबां में झांककर नहीं देखा कि वह क्या कर रहा है? जब आप अपनी आस्था पर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी सुनना पसंद नहीं करते तब आपको दूसरों के देवी-देवताओं पर अभद्र टिप्पणियां करने का अधिकार किसने दे दिया है? अच्छा ही हुआ कि वजाहत खान जैसों को आईना दिखाने के लिए हिन्दू देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने पर उनके विरुद्ध भी प्रकरण दर्ज करा दिया गया है। अब उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मोल समझ आएगा। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा है कि "लोगों को हेट स्पीच क्यों अटपटे और गलत नहीं लगते हैं। ऐसे कंटेंट पर नियंत्रण होना चाहिए। साथ ही लोगों को भी ऐसे नफरत भरे कंटेंट को शेयर करने और लाइक करने से बचना चाहिए"।

इसी प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने इंदौर के कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय के बेहद आपत्तिजनक कार्टून को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए सख्त टिप्पणी की है। न्यायालय ने कार्टूनिस्ट की मानसिकता पर प्रश्न उठाया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर बनाए गए इस आपत्तिजनक कार्टून को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि "आजकल कार्टूनिस्ट और स्टैंडअप कॉमेडियन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं। क्या ये लोग कुछ भी बनाने और बोलने से पहले सोचते नहीं है?" न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि "अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर इस प्रकार के घृणित व्यंग्य चित्रों को संरक्षण नहीं दिया जा सकता है। हेमंत मालवीय के कार्टून में कोई परिपक्वता नहीं है। ये वास्तव में भड़काऊ है"। याद हो कि इस कार्टूनिस्ट के मामले में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय भी फटकार लगा चुका है। उच्च न्यायालय ने जब कार्टूनिस्ट की जमानत याचिका खारिज की तो उसने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था लेकिन यहाँ भी उनके कृत्य पर कोई राहत नहीं मिली है। हेमंत मालवीय के कार्टून में कोई कलात्मक अभिव्यक्ति भी नहीं है। अपनी वैचारिक और राजनीतिक खुन्नस निकालने के लिए इस प्रकार के लोग कला को भी बदनाम करते हैं, जो अभिव्यक्ति की सशक्त माध्यम हैं। मजेदार तथ्य यह कि हेमंत मालवीय का बचाव कर रहे उनका भी वकील यह मानता है कि "हाँ, ये घटिया कार्टून है। लेकिन क्या ये अपराध है? नहीं, यह अपराध नहीं हो सकता। यह आपत्तिजनक हो सकता है लेकिन अपराध नहीं"। अब यह अपराध है या नहीं, यह तो न्यायालय तय करेगा लेकिन मालवीय का वकील कम से कम यह तो स्वीकार ही कर रहा है कि कार्टून घटिया है। आरोप यह हैं कि उनका कार्टून प्रधानमंत्री और एक राष्ट्रीय संगठन का अपमान ही नहीं करता है अपितु सांप्रदायिकता को भी भड़काता है। हेमंत मालवीय की शिकायत दर्ज करानेवाले सामाजिक कार्यकर्ता विनय जोशी आरोप लगाए हैं कि "मालवीय ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री अपलोड करके हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाई और सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ा"। उनकी ओर से दर्ज करायी गई एफआईआर में कई 'आपत्तिजनक' पोस्ट का उल्लेख किया गया है, जिनमें भगवान शिव पर कथित रूप से अनुचित टिप्पणियों के साथ-साथ मोदी, आरएसएस कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों के बारे में कार्टून, वीडियो, तस्वीरें और टिप्पणियाँ शामिल हैं। इससे स्पष्ट होता है कि हेमंत मालवीय ने पहली बार आपत्तिजनक कार्टून नहीं बनाया था, बल्कि यह उनका नियमित अभ्यास है। न्यायालय के अनुसार, इस प्रकार की प्रवृत्तियों को रोका जाना अत्यंत आवश्यक है।

बहरहाल, सर्वोच्च न्यायालय की इस सलाह पर नागरिक समाज को न केवल चिंतन-मनन करना चाहिए अपितु उसका अनुकरण भी करना चाहिए- "नागरिकों को अपनी बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी की कीमत समझनी चाहिए और इसके साथ-साथ स्व-नियंत्रण और संयम का पालन करना चाहिए"। सर्वोच्च न्यायालय ने तो यह भी कहा है कि सोशल मीडिया पर बढ़ती विभाजनकारी प्रवृत्तियों पर रोक लगाई जानी चाहिए। न्यायालय ने केन्द्र और राज्य सरकारों को कहा है कि वे नफरत फैलाने वाले भाषणों को रोकें। हालांकि न्यायालय ने किसी भी प्रकार की सेंसरशिप की बात से इनकार किया। यानी नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित नहीं होनी चाहिए। इसके लिए न्यायालय ने वकीलों एवं सरकारों से सुझाव भी माँगे हैं। हालांकि यह राह बहुत कठिन है कि सरकार किसी प्रकार का प्रतिबंध भी न लगाए और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर नफरती सोच पर लगाम भी लगा ले। इस दिशा में यदि कहीं कोई राह दिखायी देती है, तो वह जागरूक नागरिक समाज है। समाज को ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग को रोकने के लिए आगे आना होगा। जब नफरती भाषण करनेवालों को प्रोत्साहित करने की अपेक्षा हतोत्साहित किया जाने लगेगा, तब बहुत हद तक इस पर नियंत्रण हो जाएगा। यहाँ राष्ट्रीय विचार के कार्यकर्ताओं के धैर्य की सराहना करनी होगी कि वे नफरत की बौछारों को अनदेखा करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। जबकि अन्य विचार या संप्रदाय के प्रति अमर्यादित बयानबाजी होती है, तो तत्काल उग्र प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। शायद इसलिए ही सबने हिन्दू धर्म, हिन्दू संगठन और हिन्दू समाज को पंचिंग बैग समझ लिया है। इस पर लगाम लगनी ही चाहिए। बहरहाल, सर्वोच्च न्यायालय के इस आग्रह का पालन व्यापक स्तर पर हम सबको करना चाहिए, जिसमें न्यायालय ने कहा कि "लोग स्वयं से जिम्मेदारी निभाएं और अपनी बातों में संयम बरतें"।

अजब-गजब

OMG! 22 साल की लड़की को हो गई अजीब बीमारी, ब्रेस्ट का साइज बना शर्मिंदगी की वजह!

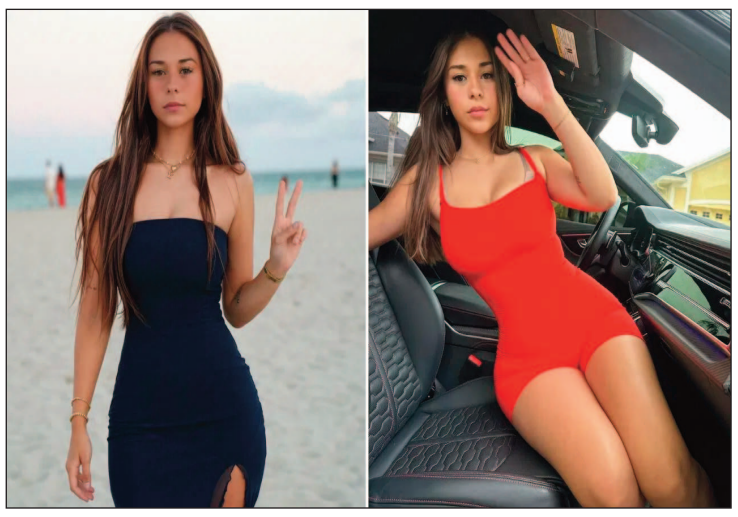

दुनिया में कई लोग होते हैं, जिन्हें कुछ अलग ही बीमारी होती है और उसका इलाज मिल पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसी ही महिला इन दिनों अजीबोगरीब बीमारी से पीड़ित है। हैरानी की बात तो ये है कि महिला के ब्रेस्ट कुछ ही दिनों में 12 किलो के हो गए। अपनी इस कहानी को जब उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया तो हर कोई दंग रह गया। हालांकि लड़की जब इसकी तह तक पहुंची तो डॉक्टरों ने उसे बताया कि ये बीमारी दुनिया में सिर्फ 300 लोगों को है।

हम बात कर रहे हैं ब्राजील की रहने वाली थैनारा मर्कॉन्डेस के बारे में, जो 22 साल की टीचिंग स्टूडेंट है। उन्होंने हाल ही में एक दुर्लभ और पीड़ादायक बीमारी से मुक्ति पाकर नई ज़िंदगी पाई है। अपनी बीमारी को लेकर उन्होंने मीडिया से बात की और कहा कि मेरे ब्रेस्ट का आकार कुछ ही महीनों में असामान्य रूप से बढ़। जिसके चलते मुझे सर्जरी करवानी पड़ी और ये तकरीबन अस्पताल में दस घंटे गया था, जिसके चलते उनकी 10 घंटे लंबी सर्जरी हुई। इस सर्जरी के दौरान मेरे ब्रेस्ट से तकरीबन (करीब 10 किलोग्राम) अतिरिक्त टिशू निकाला गया। अपने अनुभव को उन्होंने सोशल मीडिया पर भी शेयर किया। अपनी कहानी को शेयर करते हुए थैनारा ने लिखा कि पहले में मीडियम साइज की टी-शर्ट पहनती थी लेकिन अचानक बड़े ब्रेस्ट के साइज के चलते मैंने पुराने कपड़े पहनने बंद कर दिए और आखिरी में मेरी हालत ऐसी हो गई कि मुझे खुद के लिए स्पेशल ऑर्डर करके कपड़े तैयार करवाने पड़े। जिस कारण मुझे कई बार शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। अपने बारे में लड़की ने आगे कहा कि मेरी हालत तो ऐसी हो गई थी कि मैं ब्रा तक नहीं पहन पा रही थी। जिस कारण लोगों ने मुझे घूरना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो मैंने इस चीज को नजरअंदाज किया, लेकिन अंत में मुझे इसका अहसास हुआ कि ये सही नहीं है। CNN ब्राज़ील को बताया। बढ़ती छाती के कारण मुझे रोज़मर्रा की जिंदगी में काफी दूसरी तरह की तकलीफ झेलनी पड़ रही थी। कई बार दर्द इतना ज़्यादा होता कि उन्हें व्हीलचेयर की ज़रूरत पड़ती। हालांकि जब मैंने इसको लेकर डॉक्टरों से बात की तो पता चला कि मुझे गिगैंटोमैस्टिया नाम की दुर्लभ बीमारी है। जिसमें ब्रेस्ट का साइज त्यधिक और अनियंत्रित हो जाता है। हैरानी की बात तो ये है कि ये बीमारी अब तक दुनिया में सिर्फ 300 लोगों में ही पाई गई। हालांकि शुक्र की बात ये है कि इसकी जानकारी मुझे समय रहते लग गई और मैंने $7,200 (लगभग 6 लाख) की पब्लिक डोनेशन से करवाई। हालांकि डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि इस रोग में टिशू फिर से विकसित हो सकते हैं, इसलिए उन्हें नियमित निगरानी में रखा जाएगा।

ब्लॉग

समानता रिपोर्ट में बेहतरी की ओर भारत

उमेश चतुर्वेदी

इसे संयोग कहें या कुछ और, जिस समय भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आपातकाल के दिनों जोड़े गए शब्दों 'धर्मनिरपेक्ष' और 'समाजवादी' को लेकर बहस हो रही है, ठीक उसी वक्त आई विश्व बैंक की रिपोर्ट ने भारतीय समाज को ज्यादा समतामूलक बताया है। विश्व बैंक की इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत इस रैंकिंग में चोटी के चार देशों में शामिल हो गया है, जबकि दुनिया की नंबर एक और नंबर दो अर्थव्यवस्थाएं यानी अमेरिका और चीन उससे पीछे हो गए हैं। भारत से आगे स्लोवाक गणराज्य, स्लोवेनिया और बेलारूस हैं। दिलचस्प यह है कि जिस समय यह रिपोर्ट आई, ठीक उन्हीं दिनों ऑक्सफैम जैसी दूसरी एजेंसियों की ओर से आई रिपोर्टों के हवाले से भारत में बढ़ती आर्थिक आर्थिक असमानता को लेकर सवाल उठ रहे थे। ऐसे में विश्व बैंक की इस रिपोर्ट का आना और उसके समानता सूचकांक में भारत का बेहतर प्रदर्शन करना सुखद आश्चर्य का कारण तो बनता ही है।

विश्व बैंक के समानता सूचकांक को गिनी सूचकांक भी कहा जाता है। एक तरह से यह आर्थिक विकास को सामाजिक समानता से जोड़ने का सूचकांक है। इस आंकड़े के अनुसार, भारत का गिनी इंडेक्स 25.5 है। इस सूचकांक के अनुसार, भारत 'सामान्य से कम' असमानता श्रेणी में है। मानकों के अनुसार, इस श्रेणी के लिए स्कोर 25 से 30 के बीच होता है। यह 'कम असमानता' वाले समूह के मानक से कुछ ही ज्यादा है। इस श्रेणी में स्लोवाक गणराज्य शामिल है। स्लोवाक का गिनी इंडेक्स 24.1 है। इसी तरह दूसरे स्थान पर रहे सोवियत संघ के पूर्व हिस्से और मौजूदा स्लोवेनिया देश का सूचकांक 24.3 है। इसके बाद 24.4 अंकों के साथ बेलारूस है। इन तीनों के बाद भारत का नंबर है। गौरतलब है कि विश्व बैंक ने दुनिया के 167 देशों का गिनी इंडेक्स जारी किया है। इनमें भारत की स्थिति बहुत बेहतर है। विश्व बैंक की इस रिपोर्ट के अनुसार, सिर्फ़ 30 देश 'सामान्य से कम' असमानता वाली श्रेणी में आए हैं। जिनमें अत्यधिक लोक कल्याण वाले अनेक यूरोपीय देश जैसे आइसलैंड, नॉर्वे, फ़िनलैंड, बेल्जियम और पोलैंड शामिल हैं। इसमें संयुक्त अरब अमीरात जैसा धनी देश भी शामिल है। इस सूचकांक के लिहाज से भारत का प्रदर्शन विगत के डेढ़ दशक की तुलना में बहुत बेहतर है। साल 2011 में भारत का गिनी सूचकांक 28.8 था। साल 2022 में यह 25.5 पर पहुंच गया।

गिनी सूचकांक के जरिए यह समझने की कोशिश की जाती है कि देश विशेष के घरों या व्यक्तियों के बीच आय, संपत्ति और उसके उपभोग के वितरण में कितनी समानता है। इसे शून्य से लेकर 100 के सूचकांक के स्तर पर मापा जाता है। इस सूचकांक के अनुसार, जिस देश का स्कोर शून्य है, उसका मतलब है कि उस देश में पूरी तरह समानता है यानी आय का वितरण पूरे नागरिकों में समान है। इस सूची में 100 स्कोर का अर्थ है कि एक ही व्यक्ति के पास पूरी आय और संपत्ति है और वही सबसे ज्यादा उपभोग करता है, जबकि दूसरों के पास कुछ भी नहीं है। इसका मतलब यह होता है कि उस देश विशेष में पूरी तरह असमानता व्याप्त है। मोटे तौर पर समझ सकते हैं कि जिस देश का गिनी इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, उस देश में उतनी ही असमानता होगी।

विश्व बैंक का मानना है कि गिनी इंडेक्स में भारत की मजबूत स्थिति की वजह उसके गरीबी हटाओ उपाय हैं। जिनके जरिए ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में गरीबी को कम करने में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार, बीते दशक में 17.1 करोड़ लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की गई है। विश्व बैंक ने गरीबी के लिए रोजाना 2.15 अमेरिकी डॉलर से नीचे की आय को रखा है। इस लिहाज से भारत में 2011-12 के दौरान करीब 16.2 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहे थे, उनकी संख्या में साल 2022-23 में घटकर सिर्फ 2.3 प्रतिशत रह गई है।

भारत में समानता लाने में मोदी सरकार की योजनाओं का बहुत योगदान है। इसमें नई योजनाएं हैं और पुरानी का बेहतर कार्यान्वयन भी है। इन योजनाओं के जरिए लोगों तक आर्थिक पहुंच में सुधार करना, राज्य की ओर से दिए जा रहे कल्याणकारी फायदों को जमीनी स्तर तक पहुंचाना और इस पूरी प्रक्रिया में समाज के कमज़ोर और कमजोर प्रतिनिधित्व वाले समूहों का सहयोग करना है। इसमें प्रधानमंत्री जन धन योजना को पहले स्थान पर रखा जा सकता है। जिस योजना के तहत 25 जून, 2025 तक 55.69 करोड़ से ज़्यादा लोगों के पास जन धन खाते थे। इनके जरिए ना सिर्फ लोगों को राज्य की ओर से मिलने वाली कल्याणकारी योजनाओं का फायदा सीधे पहंच रहा है, बल्कि वित्तीय कामकाज के लिए बैंकों तक इन लोगों का जुड़ाव बढ़ा है। इससे लोगों की आर्थिक स्थिति सुधर रही है।

आधार और डिजिटल पहचान के जरिए कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित हुई है। तीन जुलाई, 2025 तक देश के 142 करोड़ से अधिक लोगों के आधार कार्ड जारी किए जा चुके थे। राज्य के कल्याणकारी योजनाओं का भुगतान और सब्सिडी आदि को अब सीधे लोगों के खातों में पहुंचाया जा रहा है। इसकी वजह से देश की बचत बढ़ी है। एक आंकड़े के अनुसार, मार्च 2023 तक देश की संचयी बचत 3.48 लाख करोड़ तक पहुंच चुकी थी। जाहिर है कि इनमें से ज्यादातर लोगों का पैसा प्रत्यक्ष और सीधे खातों तक वित्तीय मदद पहुंच रहा है। भारत की आर्थिक और सामाजिक असमानता को कम करने में आयुष्मान भारत योजना का भी हाथ मान सकते हैं। इसके जरिए इससे कवर परिवार को सालाना 5 लाख रूपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार तीन जुलाई, 2025 तक देशभर में 41.34 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। जिसके दायरे में देश भर के 32,000 से अस्पताल शामिल हैं। इस योजना के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों के लिए आयुष्मान वय वंदना योजना शुरू की जा चुकी है, चाहे उनकी आय जो भी हो। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की वजह से यह प्रयास और मजबूत हुआ, जिसमें लोगों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने के लिए 79 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य खाते बनाए जा चुके हैं। भारत में आर्थिक और सामाजिक असमानता को दूर करने में स्टैंड-अप इंडिया जैसी योजना के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। देश में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित इस योजना के जरिए दलित और आदिवासी एवं महिला उद्यमियों को ग्रीनफील्ड उद्योग स्थापित करने के लिए 10 लाख से एक करोड़ रूपए तक का कर्ज दिया जा रहा है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार इस साल जुलाई के पहले हफ्ते तक इस योजना के तहत पूरे देश में 2.75 लाख से अधिक आवेदन स्वीकृत किए जा चुके थे। इसके तहत नव उद्यमियों को 62,807.46 करोड़ रूपए दिये जा चुके हैं। एक तरह से इस योजना के जरिए वंचित समुदाय की आर्थिक तरक्की हो रही है। आर्थिक तरक्की की राह सामाजिक विकास को भी प्रभावित करती है।

भारत में जारी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना देश की खाद्य और सामाजिक सुरक्षा का मजबूत स्तंभ बन चुकी है। कोरोना महामारी के दौरान शुरू की गई इस योजना तहत 80.67 करोड़ लोगों को खाद्यान्न दिया जा रहा है। मुफ़्त मिल रहे खाद्यान्न का उद्देश्य है कि देश का कोई भी व्यक्ति भूखे पेट ना सोए। भारत में गरीबी कम करने में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का भी अपना विशेष योगदान मान सकते हैं। इसके तहत पारम्परिक कारीगरों और शिल्पकारों बिना किसी जमानत के ऋण, टूलकिट, डिजिटल प्रशिक्षण और मार्केटिंग सहायता दिए जा रहे हैं। इस साल जुलाई के पहले सप्ताह तक इस योजना के तहत 29.95 लाख व्यक्तियों को फायदा मिल चुका है। इससे शहरी और ग्रामीण, दोनों तरह की गरीबी दूर करनें में मदद मिली है।

इसका यह मतलब नहीं कि ऑक्सफैम की रिपोर्ट को अनदेखा कर दिया जाए। इसके अनुसार देश में आर्थिक असमानता बहुत ज्यादा है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे अमीर महज एक प्रतिशत लोगों के पास देश की चालीस फीसद से ज्यादा की संपत्ति है, जबकि सबसे गरीब आधी आबादी के पास सिर्फ तीन प्रतिशत संपत्ति है। यह असमानता आय, संपत्ति और अवसरों में भी साफ तौर पर दिखती है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के शीर्ष दस प्रतिशत लोगों के पास कुल राष्ट्रीय संपत्ति का 77 फीसद % हिस्सा है। इस रिपोर्ट के अनुसार, देश में 119 अरबपति हैं। 2000 में इनकी संख्या केवल 9 थी, जो 2017 में बढ़कर 101 हो गई और अब यह बढ़कर सौ से ज्यादा हो गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक, देश में अरबपतियों की संपत्ति में एक दशक में करीब 10 गुना की बढ़ोतरी हुई है। उनकी कुल संपत्ति वित्त वर्ष 2018-19 के भारत के केंद्रीय बजट से भी ज्यादा रहा। साफ है कि गिनी सूचकांक में भारत की स्थिति सुधरी तो है, लेकिन ऑक्सफैम की रिपोर्ट असमानता की ओर भी ध्यान दिलाती है। इसकी ओर भी ध्यान दिया जाना होगा। तभी हम सही मायन में समतामूलक और समाजवादी समाज बन सकेंगे। क्योंकि समाजवाद का मतलब पूंजी का विकेंद्रण होता है, संकेंद्रण नहीं।

बागपत में दिल दहलाने वाली घटना

महिला ने हाथ-पैर पर सुसाइड नोट में लिखे ससुराल में हुए जुल्मों-सितम, मौत

आर्यावर्त संवाददाता

छपरौली (बागपत)। एक महिला ने जहरीला पदार्थ निगलकर आत्महत्या कर ली। उसने सुसराल वालों पर दहेज में कार न मिलने पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। महिला ने अपने बाएं हाथ और पैर पर ससुराल में हुए जुल्मों-सितम को एक-एक कर लिखा। एक वीडियो में अपना दर्द सुनाते हुए तीन पन्नों का सुसाइड नोट भी लिखा।

दिल्ली नगर निगम में कर्मचारी तेजवीर सिंह निवासी रठौड़ा ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी मनीषा की शादी 26 नवंबर 2023 को सिद्धीपुर थाना दादरी, जिला गौतमबुद्धनगर निवासी कुंदन के साथ की थी। शादी में 20 लाख रुपये खर्च करते हुए

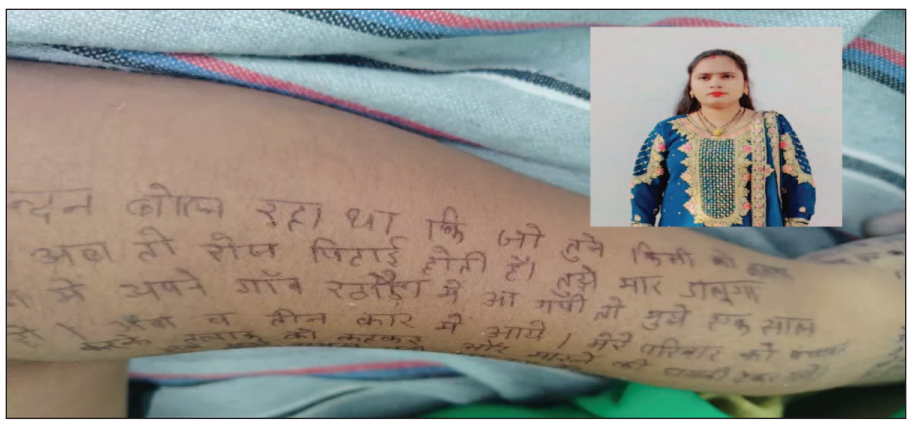

काफी सामान दिया था। शादी के बाद उसका दामाद और अन्य ससुराल वाले कार की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर तीन महीने बाद ही ससुराल में उसकी बेटी का शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न शुरू कर दिया गया।इससे तंग होकर वह मायके में आ गई। वह काफी तनाव में रहती थी। तेजवीर ने बताया कि मंगलवार रात 27 वर्षीय मनीषा छत पर सोई हुई थी। उसने परेशान होकर जहरीला पदार्थ निगल लिया। बुधवार सुबह वह नहीं जागी तो उन्होंने देखा तो वह मृत थी।

इंस्पेक्टर देवेश कुमार शर्मा ने बताया कि मनीषा ने जहरीला पदार्थ निगलकर आत्महत्या की है। मृतका के हाथ पर पेन से आत्महत्या की वजह लिखी हुई थी। उसके पास से तीन पन्नों का सुसाइड नोट मिला है और मोबाइल से 3:29 मिनट का वीडियो मिला है, जिसमें उसने पति व ससुराल पक्ष के लोगों पर उत्पीड़न करने के आरोप लगाते हुए उन्हें ही जिम्मेदार ठहराया है।

तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। उधर, मनीषा के शव का पोस्टमार्टम तीन चिकित्सकों के पैनल ने किया। इसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई।

सीएमओ कुर्सी पर फिर काबिज हुए हरिदत्त नेमी, मीडिया से बात करने से किया इनकार

आर्यावर्त संवाददाता

कानपुर। जिले के सीएमओ की कुर्सी पर चल रहा विवाद गुरुवार को थम गया। जब शासन की ओर से निलंबन पर फैसला बदलने के बाद डा. हरिदत्त नेमी ने सुबह 10 बजे सीएमओ कार्यालय में पहुंचकर सीएमओ का चार्ज संभाला।

उन्होंने एसीएमओ और एक दिन के लिए सीएमओ का चार्ज संभालने वाले डा. रमित रस्तोगी से सीएमओ का चार्ज लिया और विभागीय पत्राचार में लग गए। हालांकि इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करने से इन्कार कर दिया।

बुधवार को शासन ने पत्र जारी करते सीएमओ डा. उदय नाथ को फिर से श्रावस्ती अपर मुख्य चिकित्साधिकारी का कार्यभार संभालने और तत्कालीन सीएमओ डा. हरिदत्त नेमी के निलंबन के आदेश को स्थगित करने का पत्र जारी किया गया था। इसके बाद सीएमओ पद पर

फिर से हरिदत्त नेमी के बैठने की पर मुहर लग गई थी।

आपको बताते चले कि 19 जून को डीएम की जांच रिपोर्ट के आधार पर निलंबित हुए तत्कालीन सीएमओ डा. हरिदत्त नेमी को महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं लखनऊ कार्यालय से संबद्ध कर दिया था और उनके स्थान पर अपर मुख्य चिकित्साधिकारी श्रावस्ती के पद पर तैनात डा. उदय नाथ को कानपुर का नया सीएमओ बनाया गया था।

इसके बाद हाईकोर्ट से स्थगन के आदेश लेकर 10 जुलाई को डा. नेमी सीएमओ की कुर्सी पर काबिज हो गए थे, जो करीब 30 घंटे की मशक्कत के बाद सीएमओ की कुर्सी से हटे थे। लेकिन 16 जुलाई को जिले के सीएमओ की कुर्सी एक बार फिर पसोपेश में फंस गई। दोपहर करीब 12 बजे शासन की ओर से दो पत्र जारी किए गए।

पहले पत्र में शासन ने हाईकोर्ट पहुंचे तत्कालीन सीएमओ डा. हरिदत्त नेमी के निलंबन के आदेश को स्थगित करने और दूसरे पत्र में वर्तमान सीएमओ डा. उदयनाथ को अग्रिम आदेशों तक पूर्व की भांति अपर मुख्य चिकित्साधिकारी श्रावस्ती के पद पर तैनात रहने का निर्देश जारी किया गया। पत्र मिलते ही सीएमओ डा. उदय नाथ डीएम जितेन्द्र प्रताप सिंह से मिलने पहुंचे और वहां से सीधे सर्किट हाउस होते हुए श्रावस्ती के लिए रवाना हो गए थे।

पत्नी मीठी बातें कर बुलाती, फिर पति करता किडनैप... हुस्न के जाल में फंसे बुजुर्ग

आर्यावर्त संवाददाता

कानपुर। उत्तर प्रदेश के बांदा से एक हनीट्रैप का सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां एक महिला ने कानपुर के रहने वाले एक अधेड़ शख्स को शिकार बना लिया, महिला ने उसे फुसलाकर कानपुर से फतेहपुर बुलाया इसके बाद बंधक बनाकर उसकी सोने की चेन, अंगूठी और तीन लाख से ज्यादा का कैश लूट लिया. पीड़ित किसी तरह पुलिस के पास पहुंचा. उसने पुलिस को जो बताया उससे पुलिस के भी होश उड़ गए. पुलिस ने फिर छापेमारी कर महिला समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. उनके खिलाफ आगामी कार्रवाई जारी है.

दयाराम कानपुर नगर निगम में सफाई सुपर वाईजर हैं. वो यहां किराए का कमरा लेकर रहते हैं. इसी मकान में बांदा के चिल्ला का पिंटू अपनी कथित पत्नी मोना के साथ किराए में रहता है. इसी दौरान मोना

की दयाराम से जान पहचान हो गई. दोनों में फिर दिन भर बातचीत होने लगी. इसके बाद मोना ने अपनी मीठी-मीठी बातों से दयाराम को अपने प्रेमजाल में फंसा लिया.

11 जुलाई को मोना ने दयाराम को फोन करके कानपुर से फतेहपुर बुलाया. दयाराम भी उसके कहने पर तुरन्त फतेहपुर पहुंच गया. वहीं मोना और पिंटू सहित पांच लोगों ने मिलकर दयाराम का अपहरण कर लिया. फिर उसे बांदा के चिल्ला ले गए और उसे बंधक बनाकर तमंचे के दम पर चेन, अंगूठी और लगभग 4 लाख कैश लूट लिया.

3 लाख रुपये करवाए ट्रांसफर

बांदा के अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज ने बताया- चिल्ला थाना पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. एक अन्य की तलाश अभी जारी है. पकड़े गए आरोपियों ने नगर निगम कानपुर में तैनात सफाई सुपर वाईजर दयाराम को फतेहपुर बुलाया. जिसके बाद बंधक बनाकर तमंचे के दम पर सोने के गहने और नकदी छीन ली. इसके अलावा यूपीआई से पैसे अपने खातों में ट्रांसफर कर लिए. आरोपियों ने पीड़ित से यूपीआई के माध्यम से करीब 3 लाख ट्रांसफर कराए. कुछ पैसा एटीएम के माध्यम से भी निकाला गया. जानकारी होने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज जा रहा है. उन्होंने बताया कि इनके कब्जे से दयाराम से छीना गया सोने के गहने, 3 लाख 69 हजार कैश भी बरामद किया गया है.

माझा बरहटा के किसानों का अधिकारी कर रहे शोषण

अयोध्या। भूमि अधिग्रहण के नाम पर माझा बरहटा के किसानों का जिले के अधिकारी शोषण कर रहे जिसके लेकर भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक ने बृहस्पतिवार को तहसील सदर के तिकुनिया पार्क में किसान पंचायत लगाई गई गयी। पंचायत की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अरविंद यादव ने किया संचालन जिला महासचिव जीपी किसान ने किया। जिला अध्यक्ष अरविंद यादव के द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रसंशा की गई। किंतु मुख्यमंत्री द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों के लिए आवंटित धनराशि का जिला स्तरीय अधिकारियों के द्वारा सदुपयोग न कर दुरुपयोग किया जा रहा है। जिससे जनता में आक्रोश व्याप्त हो रहा है। जिला अध्यक्ष अरविंद यादव ने बताया कि नायब तहसीलदार को मुख्यमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन सौंपा गया। प्रदेश सचिव जगतपाल सिंह ने बताया कि किसानो की समस्याओं का निस्तारण नहीं हुआ तो जिले में राष्ट्रीय स्तर की पंचायत की जाएगी।

स्कूली बच्चों ने रैली निकालकर डायरिया के प्रति किया जागरूक

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

बदायूं। जनपद के पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय आमगांव जगत के विद्यार्थियों ने बृहस्पतिवार को जागरूकता रैली निकालकर बच्चों को डायरिया से सुरक्षित बनाने के जरूरी सन्देश दिए। डायरिया रोको अभियान के तहत पोस्टर-बैनर लेकर निकली बच्चों और उनके अभिभावकों की इस रैली का नेतृत्व प्रधानाध्यापक संगीता शर्मा ने किया। रैली के अलावा बच्चों को अन्य गतिविधियों के माध्यम से भी डायरिया के प्रति जागरूक बनाया गया। सांप-सीढ़ी खेल के माध्यम से भी उनको डायरिया से सुरक्षित रहने के प्रमुख सन्देश दिए गए। हाथों की सही तरीके से साफ़-सफाई के भी जरूरी टिप्स दिए गए और हाथों को सही तरीके से धुलने का अभ्यास भी कराया गया ।

इस मौके पर प्रधानाध्यापक संगीता शर्मा ने कहा कि भीषण गर्मी

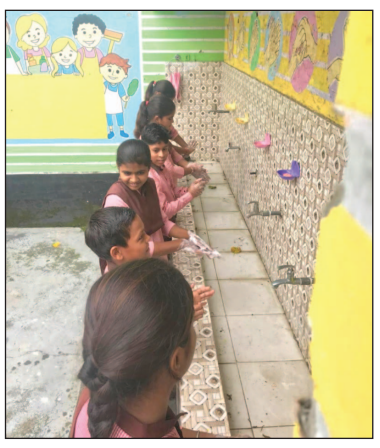

और बारिश के दौरान डायरिया के मामले बढ़ जाते हैं। डायरिया का सही इलाज ओआरएस का घोल और जिंक के टेबलेट हैं, जिन्हें उम्र के अनुसार निश्चित अवधि तक लेना बहुत जरूरी होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए जिले में 16 जून से 31 जुलाई तक डायरिया रोको अभियान चलाया जा रहा है। डायरिया रोको अभियान में पापुलेशन सर्विसेज इंटरनेशनल इंडिया (पीएसआई इंडिया) और केनव्यू भी सहयोग कर रहे हैं। समुदाय में डायरिया के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य के साथ ही बच्चों में डायरिया की रोकथाम, ओआरएस व जिंक के उपयोग को प्रोत्साहन और जनसामान्य में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए आज यह रैली निकाली गयी। इस दौरान अध्यापक समिता सक्सेना, भू प्रभा, अवधेश कुमार, गीता शर्मा, मधु पटेल, सहायक अध्यापक नरेश कुमार मौर्य, अनुदेशक मिथिलेश कुमारी, प्राची शर्मा तथा पीएसआई इंडिया की तरफ से शशांक दुबे, दानिश वर एवं बड़ी संख्या में अभिभावक भी उपस्थित रहे।

पांच लाख रुपए के अवैध गांजा के साथ एक अंतर्जनपदीय तस्कर चढ़ा जमालपुर पुलिस के हत्थे

आर्यावर्त संवाददाता

मीरजापुर। पांच लाख रुपए के अवैध गांजा के साथ एक अंतर्जनपदीय शातिर गांजा तस्कर को जमालपुर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन बर्मा द्वारा जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़, अवैध शराब एवं मादक पदार्थों के निर्माण तस्करी व बिक्री पर अंकुश लगाते हुए मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं प्रभावी कार्यवाही करने हेतु जनपद के समस्त थाना प्रभारी गण को निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के विरूद्ध अभियान चलाकर अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन व क्षेत्राधिकारी चुनार के नेतृत्व में थाना जमालपुर पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बुधवार को थानाध्यक्ष जमालपुर अमित कुमार मय पुलिस टीम द्वारा मुखबीर से प्राप्त सूचना के आधार थाना जमालपुर क्षेत्रान्तर्गत भाईपुर बाजार से 01 शातिर गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया गया । जिसके द्वारा पूछताछ में अपना नाम पता विनोद यादव पुत्र गामा यादव निवासी मुडियारी बनतरवा थाना भुडकुड़ा जनपद गाजीपुर बताया गया । मौके से बोरे में भरकर 10 बण्डलो में रखा कुल 20 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ । उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना जमालपुर पर मु0अ0सं0-112/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त विनोद यादव पुत्र गामा यादव निवासी मुडियारी बनतरवा थाना भुडकुड़ा जनपद गाजीपुर उम्र करीब -30 वर्ष है।

कांवड़ यात्रा में हॉकी स्टिक, डंडा और त्रिशूल लेकर नहीं चल पाएंगे कांवड़िये, लगा बैन

आर्यावर्त संवाददाता

सहारनपुर। कांवड़ यात्रा के दौरान हो रही मारपीट की घटनाओं और दुर्घटनाओं के मद्देनजर अब यूपी पुलिस ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। सहारनपुर रेंज के डीआईजी अभिषेक सिंह ने कांवड़ यात्रा को लेकर बने नियमों का सख्ती से पालन करवाने का अधिकारियों को निर्देश दिया है। डाक कांवड़ को लेकर भी सख्त निर्देश जारी किए गए हैं।

सहारनपुर, शामली, और मुजफ्फरनगर की ओर से कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों के लाठी-डंडे, त्रिशूल और हॉकी स्टिक लेकर चलने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा बिना साइलेंसर की बाइक भी पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है। सहारनपुर रेंज के डीआईजी अभिषेक सिंह ने रेंज के अधिकारियों से निर्देशों कांवड़ यात्रियों से कड़ाई से पालन कराने को कहा

है।

कांवडियों से नियमों का पालन कराएं: DIG

डीआईजी अभिषेक सिंह ने सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर के अधिकारियों के साथ-साथ कांवड़ यात्रा संघ से जुड़े लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीटिंग की। इसमें उन्होंने सभी से डाक कांवड़ ओर पैदल चलने वाले कांवड़ियों के लिए जो नियम बनाए गए हैं, उन सभी नियमों का पालन कांवड़ यात्रियों से करवाने के लिए कहा।

बिना साइलेंसर की बाइक का न करें उपयोग

अभिषेक सिंह ने कहा कि कोई भी कांवड यात्री यात्रा में हॉकी स्टिक, त्रिशूल, लाठी-डंडे लेकर ना चले। इसके अलावा कुछ डाक कांवड़ यात्री बिना साइलेंसर की बाइक से जाते हैं, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं हो जाती हैं। ऐसे लोग ऐसी बाइक का बिल्कुल प्रयोग ना करें वर्ना उन बाइकों को जब्त भी किया जा सकता है। बड़े वाहनों के जरिए कांवड़ लाने वाले लोग उसका साइज और डीजे की लंबाई-चौड़ाई का ध्यान रखें। गौरतलब है कि इन दिनों कांवड़ यात्रा चल रही है। उत्तर प्रदेश में जगह-जगह पर लोग कांवड़ लेकर जा रहे हैं।

दबंग कर रहे पीड़ित की जमीन पर अवैध निर्माण पीड़ित न्याय पाने के लिए तीन दिनों से लगा रहा चक्कर

आर्यावर्त संवाददाता

बलरामपुर। जिले में जहां डीएम व एसपी सख्त है और भूमाफियाओं पर लगातार कार्यवाही कर रहे हैं। वहीं देहात कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कलंदरपुर में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं, भूमाफियाओं द्वारा रामफेर पुत्र बाऊन के पुश्तैनी जमीन गाटा संख्या 143ग तथा 143 जिसमें पीड़ित द्वारा कुछ हिस्सा बिक्री किया गया था जो न्यालय में विचाराधीन है उसके बाद भी दबंगों द्वारा अवैध तरीके से शेषराम निवासी जब्दहा व उनके परिजनों द्वारा दबंगई कर जबरन कब्जा किया जा रहा है तथा पीड़ित द्वारा मना करने पर भद्दी भद्दी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दिया जा रहा है वहीं पीड़ित के द्वारा आरोप लगाया गया की कई बार देहात कोतवाली में शिकायत करने के बाद भी अवैध निर्माण नहीं रूकवाया गया वहीं कोतवाली से बीट आरक्षी को भेजा जाता है तो जबतक पुलिस रहती है तब तक निर्माण बंद रहता है और जैसे ही पुलिस हटती है निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाता है दबंगों द्वारा आखिर क्या देहात कोतवाली पुलिस किसी अप्रिय घटना का इंतजार कर रही है जब कोई बड़ी घटना घट जायेगी तब पुलिस रूकवायेगी अवैध निर्माण वहीं अवैध निर्माण न रूकना संबंधितों की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर रहा है। वहीं जब देहात कोतवाली प्रभारी से बात किया गया तो उन्होंने बताया की जांच करवा कर कार्यवाही किया जायेगा।

5वीं फेल ने बनाया गैंग, चीन के साइबर एक्सपर्ट्स से जुड़ा... लोगों से वसूले करोड़ों रुपये; 8 गिरफ्तार

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से साइबर ठगी का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। आरोपियों ने डिजिटल अरेस्ट, शेयर ट्रेडिंग और वर्कफ्राम होम के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी की। पुलिस ने ठगी करने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान दिलचस्प बात सामने आई। इस ठगी के गिरोह को चलाने वाला राहुल पांचवीं फेल है। वह टेलीग्राम के जरिए चीनी साइबर ठगों से जुड़ा था। चुराए गए पैसों को वह किराए पर लिए बैंक खातों में मगवाता था और फिर उसे क्रिप्टों और अन्य माध्यमों से चीन भेजा करता था।

पुलिस की टीम जांच में जुटी हुई है। साथ ही पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन ठगों का नेटवर्क कितने राज्यों तक फैला है। पुलिस द्वारा

गिरफ्तार किये गये आरोपियों में विनोद कुमार, मईक अहमद, मनीष जयसवाल, क्रिश शुक्ला, दिवाकर सिंह, मोहम्मद साद, सक्षम तिवारी और सत्यम तिवारी शामिल है ।विशेष इनपुट के जरिए आरोपी हिरासत में

पुलिस में बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों को विशेष इनपुट के जरिए पकड़ा गया। पुलिस ने बताया कि साइबर क्राइम व क्राइम सेल की टीम ने एक साथ मिलकर छापेमारी की गई, जिसके बाद गिरोह का भांड़ाफाड़ हुआ। छापेमारी के दौरान गिरोह के सरगना के साथ 8 लागों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। साथ ही मामले से जुड़े अन्य पहलुओं पर जांच कर रही है।

कमीशन पर होता था काम

पुलिस प्रशासन के मुताबिक गिरोह के सभी लोगों का काम बंटा हुआ था। उसी हिसाब से सबको अलग-अलग कमीशन मिलता था। जानकारी का मुताबिक गिरोह के तालुकात चीन से है। ये चीनी साइबर ठग वहीं से ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे। उनके इसारे पर ये आरोपी काम किया करते थे। सबूतों के आधार पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है।

आरोपियों के पास से क्या मिला

आरोपितों के पास से पुलिस ने 16 मोबाइल फोन, दो लैपटॉप, एक टैब, तीन चेक बुक, एक पास बुक और 185000 रुपये बरामद किए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरोपियों ने 20 करोड़ रुपये से ज्यादा की ठगी को अंजाम दिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी लोगों को ट्रेडिंग और अन्य तरीकों से साइबर फ्रॉड में फंसाते थे और ठगी की रकम किराये पर लिए गए अकाउंट में मगवाकर फौरन फेर बदल कर लेते थे। ताकि बैंक को सक ना हो और अकाउंट फ्रीज होने से बच जाए।

स्वच्छता रैंकिंग में अयोध्या की लंबी छलांग, 28वें पायदान पर पहुंचा

अयोध्या। स्वच्छ भारत मिशन 2024- 25 के सर्वे में पूरे देश में 28 वीं रैंक हासिल कर अयोध्या ने स्वच्छता के पैमाने पर पूरे देश में लंबी छलांग लगाई है। वर्ष 2023-24 में अयोध्या रैंकिंग के मामले में 100वें पायदान पर था। स्वच्छ भारत मिशन की इस उपलब्धि पर महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी एवं नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार ने मिशन से जुड़ी टीम की सराहना की है। अयोध्या नगर निगम ने लगातार चार वर्षों से स्वच्छता के पैमाने पर अपनी रैंकिंग में निरंतर सुधार किया है।

प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ के दौरान अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आने के चलते आई चुनौती के बावजूद इस बार उसकी रैंकिंग पूरे देश में 28 वीं रही। उसे इस वर्ष मई माह में हुए स्वच्छता सर्वेक्षण के कुल पूर्णांक 12500 में 9291 अंक मिले, जो 74 फीसदी रहा, जबकि वर्ष 2023 में उसे 73 फीसदी अंक प्राप्त हुए थे।

प्रयागराज के स्कूल में चाकूबाजी, छठी क्लास के बच्चे ने सीनियर को मारा चाकू... किए कई वार

आर्यावर्त संवाददाता

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के एक प्राइवेट स्कूल में एक छठी क्लास के बच्चे ने 8वीं क्लास के एक छात्र पर चाकू से हमला कर दिया। इससे स्कूल में हड़कंप मच गया। स्कूल के अंदर हुई घटना से शिक्षकों और दूसरे बच्चों में अफरा-तफरी मच गई। घटना के बाद 8वीं क्लास का छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल छात्र की मां ने थाने में शिकायत दर्ज कराई।

धूमनगंज थाना क्षेत्र के हरवारा मोहल्ले में रहने वाले श्याम कुमार झूंसी स्थित दुर्वासा इंटर कालेज में असिस्टेंट क्लर्क हैं। उनका बेटा दक्ष भारतीय धूमनगंज स्थित एक प्राइवेट स्कूल में 8वीं क्लास में पढ़ता है। पिता ने बताया कि उनका बेटा स्कूल गया था। करीब 10 बजे लंच के टाइम वह परिसर में सहपाठियों के साथ बातचीत कर रहा था। इसी

दौरान छठी क्लास का एक छात्र आया और गाली-गलौज करने लगा।

पीठ पर कई बार किया वार

उन्होंने आगे बताया कि जब बेटे ने विरोध किया तो छठी क्लास के छात्र ने चाकू निकाल लिया और बेटे की पीठ पर कई बार वार किया। ऐसे में बचने के लिए जख्मी हालत में दक्ष चीख-पुकार मचाते हुए प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंचा। तब जाकर उसकी उसकी जान बचाई गई। उसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इसके बाद दक्ष की मां मनीषा देवी ने धूमनगंज थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दी।

पुलिस मामले की जांच में जुटी

पीड़ित परिवार ने बताया कि आरोपित छात्र का कुछ दिन पहले ही स्कूल में एडमिशन हुआ था। वह स्कूल में चाकू लेकर कैसे घुसा। इसको लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल धूमनगंज के इंस्पेक्टर अमरनाथ राय का कहना है कि घटना की जानकारी मिली है। एक प्राइवेट स्कूल में छठी क्लास के छात्र ने 8वीं क्लास की छात्र पर चाकू से हमला किया है। छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसकी हालत गंभीर है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

थायराइड की समस्या आजकल काफी आम होती जा रही हैं . कुछ लोगों का इसके कारण वजन बढ़ने लगता है . जिसे कम करने में उन्हें काफी परेशानी होती है . अगर आपको भी थायराइड है और वजन कम नहीं कर पा रहे हैं, तो एक्सपर्ट से जानें इसका कारण और टिप्स के बारे में

थायराइड में क्यों बढ़ जाता है वजन, एक्सपर्ट से जानें इसे कम करने का तरीका

आजकल भागदौड़ से भरी जिंदगी, गलत खानपान और अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण बहुत सी बीमारियां आम होती जा रही हैं। जिनमें थायराइड की समस्या भी शामिल है। महिलाओं में ये समस्या ज्यादा देखी जाती है। थायराइड एक तरह का एंडोक्राइन ग्लैंड है जो गले में बिल्कुल सामने की ओर तितली के आकार में होता है। थायराइड ग्रंथि के ज्यादा या कम मात्रा में हार्मोन होने पर थायराइड की समस्या पैदा होती है।

जबथायराइड ग्लैंड आपके शरीर में जरूरत से ज्यादा थायराइड हार्मोन बनाती है। तो इस कंडीशन को हाइपरथायरायडिज्म कहते है वहीं जब थायराइड ग्लैंड पर्याप्त मात्रा में थायराइड हार्मोन नहीं बना पाता है। तब इस स्थिति हाइपोथायरायडिज्म कहा जाता है। हाइपरथायरायडिज्म के मुख्य लक्षण वजन घटता है और हाइपोथायरायडिज्म की वजह से वजन बढ़ने लग सकता है। ज्यादातर लोगों में वजन बढ़ने की समस्या देखी जाती है।

थायराइड के कारण कई लोगों का वजन बढ़ जाता है, जिसे कम करने के लिए वह कई प्रयास करते हैं। लेकिन इसके बाद भी कुछ खास असर दिखाई नहीं देता है। अगर आप भी कई कोशिशें करने के बाद वजन कम नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके पीछे ये कारण हो सकता है। आइए जानते हैं इसके बारे में एक्सपर्ट से

क्या कहती हैं एक्सपर्ट?

दिल्ली के श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट में प्रिंसिपल कंसलटेंट, एंडोक्राइनोलॉजी एंड ओबेसिटी मेडिसिन डॉक्टर साकेत कांत ने बताया कि थायराइड की समस्या के कारण वजन कम न होना आम लेकिन परेशान करने वाली स्थिति है। जब थायराइड ग्रंथि ठीक तरह से काम नहीं करती, तो ऐसे में शरीर का मेटाबॉलिज्म धीमा होने लगता है, जिससे कैलोरी बर्न करने की क्षमता कम हो जाती है। जिसके कारण सही डाइट और एक्सरसाइज के बावजूद भी वजन कम करना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा शरीर में हार्मोनल असंतुलन होने के कारण भूख में बदलाव, मानसिक तनाव और थकान जैसी समस्या बढ़ सकती है, जिससे वजन कम करने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।

इन बातों का रखें ध्यान?

एक्सपर्ट का कहना है कि थायराइड के मरीजों को नियमित रूप से अपने हार्मोन स्तर की जांच करवानी चाहिए। इसके साथ ही डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही आपको दवाइयां लेनी चाहिए। क्योंकि सही हार्मोन संतुलन ही वजन को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसके साथ ही हल्की-फुल्की एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करें, इसके लिए आप मेडिटेशन या फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट तकनीक अपना सकते हैं। इसके साथ ही धैर्य करें क्योंकि थायराइड के कारण वजन कम होने में समय लग सकता है। लेकिन अगर सही डाइट और एक्सरसाइज के बाद भी वजन कम नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर से संपर्क करें। वह सही इलाज और खानपान में बदलाव के बारे में आपको सही जानकारी देंगे।

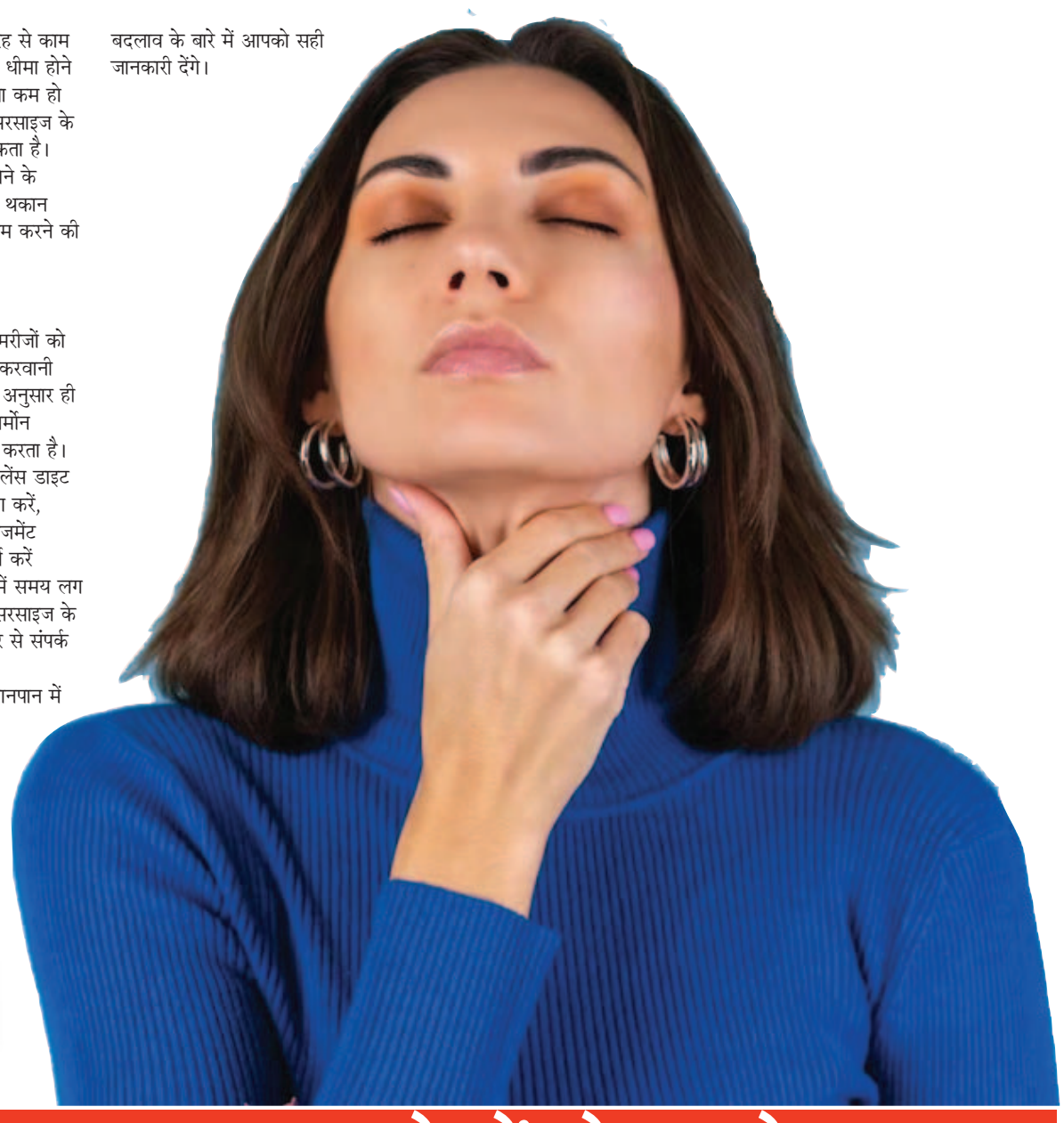

खुद को स्टाइल करते वक्त ध्यान रखें ये 4 बातें, मिलेगा परफेक्ट बॉडी शेप

अमूमन महिलाओं की चाहत होती है को पतली दिखें. लेकिन कई बार वो कुछ ऐसा पहन लेती हैं , जो उनके पूरे लुक को बिगाड़ देता है। तो अगर आप भी किसी भी आउटफिट में स्लीम दिखना चाहती हैं तो हम आपको लिए कुछ टिप्स लेकर आए हैं, जिन्हें फॉलो करके एक परफेक्ट लुक पा सकती हैं।

एक परफेक्ट फिगर और स्लीम बॉडी किसे नहीं पसंद होती है। खासतौर पर महिलाएं चाहती हैं को वो हर कपड़ो में अच्छी और पतली दिखें। लेकिन कई बार महिलाएं खुद को स्टाइल करते वक्त कुछ ऐसी गलतियां कर बैठती हैं, जिससे उनका पूरा लुक खराब हो जाता। वहीं, कुछ कपड़े उनके बॉडी शेप को खराब दिखाते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपने लिए कपड़े चुनते समय कुछ अहम बातों का ध्यान रखें।

शॉपिंग करते हुए सिर्फ कपड़े का डिजाइन या कलर ही देखना काफी नहीं होता है। वो आपकी बॉडी टाइप पर कैसा दिखेगा ये ध्यान में रखना भी जरूरी है। साथ ही आप उसे किस तरह स्टाइल कर सकती हैं। तो चलिए आज इस आर्टिकल में बताते हैं कि कैसे खुद को स्टाइल कर के आप किसी भी आउटफिट में स्लीम दिख सकती हैं।

शेपवियर का करें इस्तेमाल

अगर आप अपना फिगर फ्लॉन्ट करना चाहती हैं या पतली दिखना चाहती हैं तो सबसे पहले एक अच्छे से शेप वियर में इंवेस्ट करें। शेपवियर किसी भी बॉडी टाइप को एक अलग ही लुक देता है। अगर आप बॉडीकोन ड्रेस पहन रही हैं तो शेपवियर का इस्तेमाल जरूर करें। वहीं, साड़ी से लेकर अनारकली सूट के नीचे भी आप शेप वियर पहन कर स्लीम लुक पा सकती हैं।

कपड़े खरीदते समय पैटर्न का रखें ध्यान

कपड़े का डिजाइन और पैटर्न भी एक अहम भूमिका निभाता है। इसलिए जब भी शॉपिंग के लिए जाएं तो खुद के लिए हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप वाले कपड़े न चुने। ये बॉडी को चौड़ा दिखाते हैं, जिससे आप मोटी लग सकती हैं। इसलिए खुद के लिए वर्टिकल स्ट्राइप वाली ड्रेसिस या सूट -साड़ी चुने। ये लुक को स्लीम दिखाने में काफी हद तक मदद करती हैं।

लूज कपड़े पहनना करें अवॉयड

आज कल ओवरसाइज्ड कपड़ों का काफी ट्रेंड हैं। ऐसे में ट्रेंड फॉलो करने के चक्कर में महिलाएं भी ओवरसाइज्ड कपड़े पहन रही हैं, जो उन्हें मोटा दिखा सकते हैं। इसलिए अगर आप खुद को स्लीम दिखाना चाहती हैं ओवरसाइज्ड कपड़ों को पहनने से बचें और फिटेड कपड़ों को चुनें।

लॉन्ग कुर्ती-हाईवेस्ट बॉटम

जब भी ट्रेडिशनल आउटफिट पहनें तो शॉर्ट कुर्ती के बजाए लॉन्ग कुर्ती चुने। ये बॉडी को लंबा दिखाने के साथ ही स्लीम लुक भी देती है। वहीं, आप लो- वेस्ट बॉटम की जगह हमेशा हाईवेस्ट बॉटम को चुनें। हाईवेस्ट बॉटम पेट के फैट को छिपा देती हैं जिससे हाइट को बढ़ी दिखती ही है। साथ ही स्लीम लुक भी आता है।

50-100 रुपये में दोस्त हो जाएगा खुश, ये गिफ्ट आइडियाज हैं बेस्ट

फ्रेंडशिप जे दोस्तों के लिए एक खास दिन होता है । इस दिन दोस्त एक दूसरे को गिफ्ट्स देकर स्पेशल फील करवाते हैं । तो अगर आप भी इस खास मौके पर अपने किसी दोस्त को कुछ देने का सोच रहे हैं और आपका बजट कम हैं तो हम आपके लिए बेस्ट गिफ्ट्स ऑप्शन लेकर आए हैं ।

हैंडमेड

हर साल अगस्त के पहले रविवार को फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है। इस साल Friendship Day 3 अगस्त को मनाया जाएगा। ये दिन सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि उन रिश्तों की अहमियत को सलाम करने का मौका है, जो खून के रिश्तों से कहीं गहरे होते हैं। स्कूल की बेंच से लेकर ऑफिस की कॉफी टेबल तक, जिंदगी के हर पड़ाव पर कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो हमारे दुख-सुख के साथी बन जाते हैं। यही होते हैं हमारे दोस्त।

लेकिन आज की दौड़ती-भागती जिंदगी में हम अक्सर अपने करीबियों को अपनेपन का एहसास नहीं करा पाते। ऐसे में फ्रेंडशिप डे एक सुनहरा मौका होता है जब आप अपने दोस्तों को ये जता सकते हैं कि वे आपके लिए कितने खास हैं और क्या हो अगर इस मौके को खास बनाने के लिए एक प्यारा-सा गिफ्ट भी साथ हो? अगर आप भी सोच रहे हैं कि इस बार फ्रेंडशिप डे पर अपने दोस्तों को क्या दें, तो हम आपके लिए बजट फ्रेंडली गिफ्ट्स आइडियाज लेकर आए हैं।

गिफ्ट्स हैं बेस्ट

इस फ्रेंडशिप डे अगर आप भी अपने दोस्त को कुछ देने का सोच रहे हैं तो वो भी बिना पैसे खर्च किए तो उसके लिए कस्टमाइज्ड गिफ्ट्स एक बेहतरीन ऑप्शन है। इसें आप उन्हें खुद अपने हाथों से कोई कार्ड बनाकर दे सकते हैं। या फिर कोई पर्ल का ब्रेसेलट या नेकलेस भी देने के लिए बढ़िया रहेगा। इसमें ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे और आपका दोस्त भी खुश हो जाएगा।

फ्रेंडशिप बैंड रहेगा सबसे बेस्ट

फ्रेंडशिप डे फ्रेंडशिप बैंड देने की परंपरा तो लंबे समय से चली आ रही है। इस खास मौके पर दोस्त एक दूसरे को फ्रेंडशिप पर पहनाते हैं। दोस्ती के इस दिन पर ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। ये बहुत ही कम पैसों में आपको मार्केट में मिल जाएगा। साथ ही ये आप मेल या फीमेल किसी भी दोस्त को दे सकते हैं। फ्रेंडशिप बैंड एक अलग ही एसहास देता है जो दोस्ती के रिश्ते को और गहरा करता है।

रिंग भी है अच्छा ऑप्शन

डशिप डे पर आप अपने दोस्त को रिंग भी दे सकते हैं। आज कल मार्केट में कई तरह की यूनिक रिंग्स मिल रही हैं जो ट्रेंड में भी है। सबसे खास बात ये काफी कम पैसों में आप को मिल जाएगी। 50 से 100 रुपये के अंदर आपको एक बढ़िया सी रिंग मिल सकती है, जो आपके दोस्त के लिए किसी कीमती तोहफे से कम नहीं होगी।

सेंटेड कैंडल भी दे सकते हैं

फ्रेंडशिप डे के लिए आप सेंटेड कैंडल भी अपने दोस्त को दे सकते हैं। सेंटेड कैंडल का गिफ्ट करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। ये आपको 50 से 100 रुपये में आराम से मिल जाएगी। साथ ही , जब भी आपका दोस्त इसे अपने कमरे या ऑफिस में जलाएगा तो उसकी खूशबू से आपको जरूर याद करेगा।

अब एक साथ निकाल पाएंगे ईपीएफ का पूरा पैसा! सरकार बना रही ये बड़ा प्लान

केंद्र सरकार ईपीएफ नियमों में बड़ा बदलाव कर हर 10 साल में जमा राशि की पूरी या बड़ी निकासी की सुविधा देने पर विचार कर रही है। इससे कर्मचारी रिटायरमेंट का इंतजार किए बिना अपनी मेहनत की कमाई निकाल सकेंगे। प्रस्ताव अभी विचाराधीन है।

केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के नियमों में भारी बदलाव की तैयारी में है। अब ईपीएफ खाताधारक हर 10 साल में अपनी जमा रकम का बड़ा हिस्सा या पूरी राशि निकाल सकेंगे। यानी अब रिटायरमेंट तक इंतजार करने की जरूरत नहीं! इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक खबर के मुताबिक सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफ) के इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही है, जिससे नौकरीपेशा लोगों को अपनी मेहनत की कमाई को अपने जरूरत के हिसाब से निकाल पाएंगे।

अभी क्या है नियम?

फिलहाल ईपीएफ से पूरी रकम निकालने के लिए दो ही रास्ते हैं। पहला, जब आप रिटायर हों, यानी 58 साल की उम्र में। दूसरा, अगर आप दो महीने से ज्यादा समय तक बेरोजगार रहें। इसके अलावा कुछ खास जरूरतों, जैसे घर खरीदना, इलाज, शादी या बच्चों की पढ़ाई के लिए ही आंशिक निकासी की इजाजत है। लेकिन नए प्रस्ताव से ये सख्ती खत्म हो सकती है।

युवाओं को मिलेगी राहत?

अगर ये नियम लागू होता है, तो 30 या 40 की उम्र में भी लोग अपनी ईपीएफ रकम निकाल सकेंगे। हालांकि, एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि सरकार शायद पूरी राशि की जगह 60% तक निकासी की सीमा तय कर सकती है। ये अभी विचाराधीन है। इसका मतलब है कि युवा कर्मचारी अपनी जरूरतों, जैसे घर खरीदने या बिजनेस शुरू करने के लिए फंड का इस्तेमाल कर सकेंगे।

सरकार की मंशा क्या?

सरकारी अधिकारी के मुताबिक, पिछले कुछ समय से ईपीएफ नियमों में ढील देने का मकसद यही है कि खाताधारकों को अपने पैसे का इस्तेमाल आसानी से करने की छूट मिले। हर 10 साल में निकासी का प्रस्ताव भी इसी सोच का हिस्सा है। सरकार चाहती है कि लोग अपनी मेहनत की कमाई को अपनी जरूरतों के हिसाब से इस्तेमाल कर सकें।

एक्सपर्ट्स ने बताया फायदा या नुकसान

कुछ एक्सपर्ट इस बदलाव को लेकर उत्साहित नहीं हैं। उनका कहना है कि ईपीएफ का असली मकसद रिटायरमेंट के लिए सुरक्षित फंड तैयार करना है। बार-बार निकासी की छूट से लोग भविष्य की बचत को कम कर सकते हैं। Saraf and Partners के पार्टनर अक्षय जैन कहते हैं, ऐसे नियमों को बहुत सोच-समझकर बनाना होगा, ताकि छोटी-मोटी जरूरतें रिटायरमेंट की सुरक्षा पर भारी न पड़ें।

वहीं, King Stubb & Kasiva के पार्टनर रोहिताश्व सिन्हा का मानना है कि इससे रियल एस्टेट जैसे सेक्टर में पैसा बढ़ेगा, जिससे अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि बार-बार निकासी से रिटायरमेंट के लिए बचत कम हो सकती है।

IT सिस्टम में आ सकती है दिक्कत

एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि EPFO को अपने IT सिस्टम को और मजबूत करना होगा। मौजूदा सिस्टम इतने सारे निकासी अनुरोधों को संभालने के लिए तैयार नहीं है। अगर सिस्टम में गड़बड़ी हुई, तो धोखाधड़ी का खतरा भी बढ़ सकता है।

हाल ही में हुए बदलाव

ईपीएफने हाल ही में कुछ और ढील दी है। जुलाई 2025 से खाताधारक अपनी ईपीएफ रकम का 90% तक घर बनाने या जमीन खरीदने के लिए निकाल सकेंगे। पहले इसके लिए 5 साल तक योगदान जरूरी था, जिसे अब घटाकर 3 साल कर दिया गया है। इसके अलावा, ऑटो-सेटलमेंट की सीमा भी ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी गई है। इससे आपात स्थिति में फंड जल्दी मिल सकेगा।

ईपीएफ है क्या?

EPF यानी कर्मचारी भविष्य निधि, भारत की सबसे बड़ी रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है। इसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों अपने वेतन का एक हिस्सा जमा करते हैं, जिस पर ब्याज भी मिलता है। इसका मकसद रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा देना है। अगर ये नया नियम लागू होता है, तो ये ईपीएफ के इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव होगा।

छोटे उद्योगों को आर्थिक झटकों से बचाकर रफ्तार देने में मददगार, कॉन्ट्रैक्ट दिलाने में भी सहायक

व्यापक कवर वाली बीमा पॉलिसी का अभाव छोटे उद्योगों के टिकाऊ बने रहने और आगे बढ़ने की राह में बड़ा रोड़ा है। वह भी तब, जब देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार में इनकी बड़ी भूमिका है। ऐसे में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाकर कारोबार को रफ्तार देने में संपत्ति बीमा छोटे उद्योगों के लिए मददगार साबित हो सकती है।

बिजली गिरने से लेकर दंगों से होने वाले नुकसान पर भी मुआवजा

2013 में चक्रवात फैलिन और पुरी जिले में आई बाढ़ से एसएमई को 1.48 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। यानी हर उद्यम को औसत 1.26 लाख का झटका लगा।

यही कारण है कि संपत्ति बीमा महत्वपूर्ण हो जाता है, जो सुनिश्चित करता है कि औद्योगिक इकाइयों, गोदामों, शैक्षणिक संस्थानों और होटलों जैसे विभिन्न संपत्ति जोखिमों के लिए व्यापक कवरेज मिले।

संपत्ति बीमा आग लगने, बिजली गिरने, विस्फोटों, दंगों, हड़तालों, तूफानों, आंधी, सुनामी और भूस्खलन से होने वाले नुकसान के लिए कवरेज देता है। अगर व्यवसाय के मालिक ने संपत्ति बीमा का विकल्प चुना है तो उसे भवन, संपत्ति या उपकरण के नुकसान की भरपाई मिलेगी।

अगर बीमित व्यक्ति का व्यवसाय बाधित होता है, तो उन्हें कारोबार बंद होने के कारण हुई आय या लाभ की हानि की भरपाई मिलेगी। एक बार जब व्यवसाय मालिक को इन सबके लिए मुआवजा मिल जाता है, तो उसके लिए अपने छोटे उद्यम को फिर से पटरी पर लाना आसान हो जाता है।

व्यापक सामान्य देयता बीमा

यह पॉलिसी छोटे उद्यमों को कानूनी देनदारियों का सामना करने पर सुरक्षा प्रदान करती है। अगर उनके उत्पादों के कारण किसी थर्ड पार्टी को शारीरिक नुकसान पहुंचता है या उनके परिसर में किसी थर्ड पार्टी को चोट पहुंचती है, तो बचाव लागत के अलावा यह पॉलिसी पीड़ित पक्षों को दिए गए हर्जाने को भी कवर करती है।।

होटल, कार्यक्रम स्थल, शोरूम, रेस्तरां या कार्यालय जहां आगंतुकों की अधिक संख्या होती है, वे भी इस पॉलिसी से लाभान्वित हो सकते हैं। यह पॉलिसी न सिर्फ थर्ड पार्टी को चोट लगने/मृत्यु होने की स्थिति में सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि प्राथमिक इलाज के लागत की भरपाई भी करती है।

कॉन्ट्रैक्ट दिलाने में भी काफी सहायक

हर बीमा पॉलिसी व्यवसाय की जरूरतों के अनुसार तैयार की जाती है। इसका निश्चित प्रीमियम नहीं होता। कई ग्राहक और व्यावसायिक सहयोगी तभी कान्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, जब वह व्यवसाय देयता बीमा पॉलिसी से लैस हो। इसलिए, अगर किसी एसएमई के पास पहले से ही यह बीमा कवरेज है, तो इससे उसके व्यवसाय को बढ़ावा मिलता है। - गुरदीप सिंह बत्रा, प्रमुख, प्रॉपर्टी, रिस्क इंजीनियरिंग एंड ग्लोबल अकाउंट्स

अलास्का में 7 .3 तीव्रता का भूकंप, हिलते घर और गाड़ियों का वीडियो वायरल

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राज्य अलास्का में गुरुवार तड़के सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 7।3 रही। इसके बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई। हालांकि इसे कुछ ही घंटों के बाद वापस ले लिया गया। इस भूकंप का केंद्र अलास्का के पॉपोफ आइलैंड पर सैंड पॉइंट के पास था, जिसका केंद्र जमीन से 36 किलोमीटर नीचे था।

अलास्का भूकंप के लिहाज से सबसे सक्रिय राज्य है। यह घटना प्रशांत प्लेट और उत्तरी अमेरिका प्लेट के टकराव के कारण हुई। सुनामी का खतरा टल गया है, पर भूकंप से हुई क्षति की जानकारी अभी नहीं आई है। इससे पहले 16 जुलाई को भी अलास्का में 5।1 तीव्रता का भूकंप आया था।

सस्पेंड IAS अभिषेक प्रकाश की बढ़ीं मुश्किलें, घूसखोरी और जमीन अधिग्रहण घोटाला मामले में चार्टशीट दाखिल

भूकंप के बाद, Alaska Earthquake Center ने तटीय अलास्का के कुछ इलाकों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की थी। हालांकि, लगभग एक घंटे बाद, खतरा कम होने पर चेतावनी को केवल रद्द कर दिया गया। बाद में, मौसम एजेंसी ने सभी सुनामी चेतावनियां, सलाह, निगरानी या खतरे रद्द कर दिए।

अलास्का अर्थक्यूक सेंटर की तरफ से भूकंप के दौरान का एक वीडियो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया गया। इस वीडियो के साथ लिखा कि हमें भूकंप का यह वीडियो सैंड पॉइंट के एक निवासी ने भेजा। यह भूकंप के केंद्र से लगभग 50 मील दूर है। हम उन लोगों के आभारी हैं जिन्होंने अपने अनुभव हमारे साथ शेयर किए हैं। इससे दूसरों को समझने में मदद मिलती है कि भूकंप कैसा होता है और वे बेहतर तैयारी कर सकते हैं। जिस वीडियो को सेंटर की तरफ से पोस्ट किया गया वह महज 6 सेकंड का है। हालांकि इसमें भूकंप के कारण पार्किंग में खड़ी कारों को साफ तौर पर हिलते हुए देखा जा सकता है।

अलास्का में लगते रहते हैं भूकंप के झटके

अलास्का में जैसे ही भूकंप के झटके महसूस किए गए लोग घरों से बाहर निकल आए। भूकंप से बचने के लिए लोग सड़कों पर जमा हो गए। अलास्का में अक्सर ही भूकंप के झटके महसूस किए जाते रहे हैं। रिपोर्ट की मानें तो दुनिया के लगभग 11% भूकंप अलास्का में ही आते हैं। इस भूकंप से पहले 16 जुलाई को भी झटके महसूस किए गए थे।

अमेरिकी राष्ट्रपति और पुतिन की दोस्ती खत्म कराने के पीछे है इस महिला का हाथ

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रूस और पुतिन को लेकर बदली सोच ने सबको चौंका दिया है। वही ट्रंप जो कभी पुतिन की तारीफ करते नहीं थकते नहीं। उन्हें जीनियस और स्मार्ट कहते थे। उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्की की भी कई बार खुले मंच से आलोचना की थी। लेकिन अब वही ट्रम्प यूक्रेन को हथियार, फंडिंग और डिप्लोमैटिक सपोर्ट देने में सबसे आगे हैं। नाटो को पहले कमजोर कहने वाले ट्रम्प अब नाटो के साथ मजबूती से खड़े दिख रहे हैं।

मगर ये बदलाव किसी जियो-पॉलिटिकल एक्सपर्ट की सलाह या सुरक्षा एजेंसी की ब्रीफिंग का नतीजा नहीं है। इसके पीछे नाम है अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप का। TV9 को व्हाइट हाउस के करीबी सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी इस बदलाव की असली वजह बताती है। व्हाइट हाउस के करीबी सूत्रों ने बताया कि इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह मेलानिया ट्रंप हैं। वो अक्सर ट्रंप को याद दिलाती हैं कि यूक्रेन में मासूमों की जान जा रही है। ट्रंप के विदेश नीति सलाहकारों के साथ मेलानिया ने कई बैठकों में हिस्सा भी लिया और साफ कहा कि पुतिन से नरमी मतलब मासूमों की मौत पर चुप्पी। मेलानिया स्लोवेनिया में जन्मी हैं जो कि एक पूर्वी यूरोपीय देश है जो सोवियत प्रभाव में था लेकिन रूस से दूरी बनाए रखता था। उनका अनुभव उन्हें रूस की आक्रामक नीतियों की गहरी समझ देता है।

2022 में ही दिखने लगे थे संकेत

जब रूस ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमला किया था, तब ट्रंप ने भले ही पुतिन को सैवी कहकर संबोधित किया हो, लेकिन मेलानिया ने उसी वक्त ट्विटर पर लिखा था कि यह युद्ध भयावह है। मेरी प्रार्थनाएं यूक्रेन के साथ हैं। उन्होंने रेड क्रॉस के लिए दान की अपील भी की थी और पहली बार किसी अंतरराष्ट्रीय संकट पर इतनी स्पष्ट राय रखी थी। ट्रंप की सोच में बदलाव वहीं से शुरू हुआ।

व्हाइट हाउस की बदली हवा

2025 में ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद यूक्रेन को लेकर अमेरिका की नीति में बड़ा बदलाव आया। यूक्रेन को मिलने वाली मदद और रूस पर बढ़ते अमेरिकी दबाव में मेलानिया का इनपुट साफ दिखता है। सूत्रों के मुताबिक, मेलानिया ने स्पष्ट कहा है कि अगक अमेरिका को लोकतंत्र का नेता कहलाना है तो यूक्रेन जैसे देशों की रक्षा करनी ही होगी।

ज़ेलेन्स्की की उम्मीद बन गई हैं मेलानिया?

आज जब ट्रंप रूस के खिलाफ कड़े बयान देते हैं और अमेरिकी मिसाइलें यूक्रेन की रक्षा कर रही होती हैं, तो इसके पीछे मेलानिया की संवेदनशील सोच और नैतिक दबाव को नजरअंदाज़ नहीं किया जा सकता। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेन्स्की के लिए मेलानिया शायद व्हाइट हाउस की सबसे मजबूत उम्मीद बन चुकी हैं।

मास्को में भी हलचल, क्रेमलिन रख रहा नजर

रूस को भी व्हाइट हाउस के इस बदले रुख की भनक लग चुकी है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप किनके प्रभाव में हैं। हालांकि उन्होंने मेलानिया का नाम नहीं लिया, लेकिन EU और NATO के प्रभाव की बात करके लावरोव ने स्लोवेनिया (मेलानिया का देश) की ओर इशारा जरूर किया।

ड्रग की वजह से अमेरिका ने चीन को दी 'मौत की सजा' की धमकी, वो कितना खतरनाक है?

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे चीन के साथ एक ऐसा समझौता करना चाहते हैं जिसमें फेंटालिन बनाने और अमेरिका में भेजने वाले लोगों को सीधे मौत की सजा दी जाए। उनका दावा है कि चीन की कंपनियां जानबूझकर ऐसी केमिकल्स स्पलाई करती है जिससे ये जानलेवा ड्रंग बनती है। ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने चीन पर जो 20 फीसदी टैरिफ लगाया था वो असल में फेंटालिन पेनल्टी है।

ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने चीन पर ड्रग संकट को हवा देने का आरोप लगाया हो। लेकिन इस बार मामला और बी गंभीर है। ट्रंप का कहना है कि अगर चीन नहीं सुधरा तो अमेरिका अकेले ही इस ड्रग के खिलाफ बड़ा एक्शन लेगा। ट्रंप का दावा है कि उनके कार्यकाल में चीन के साथ इस पर एक डील होने ही वाली थी, लेकिन चुनाव चोरी के चलते वो मुमकिन नहीं हो पाया। अब वे दोबारा सत्ता में आने पर

फेंटानिल पर युद्धस्तर पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। लेकिन फेंटानिल है क्या? क्यों इतनी खतरनाक है? कैसे ये छोटे-छोटे पार्सलों में चीन से अमेरिका पहुंचती है और हर साल हज़ारों जानें ले लेती है?

फेंटानिल: पेन्सिल की नोक जितनी डोज़, और मौत तय

फेंटानिल एक सिंथेटिक ओपिऑइड (नशीली दवा) है, जिसे 1960 के दशक में मेडिकल पेनकिलर के तौर पर मंज़ूरी मिली थी। डॉक्टर ऑपरेशन के दौरान इसकी सीमित डोज का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन गड़बड़ वहां से शुरू होती है जहां ये दवा मेडिकल सिस्टम से निकलकर इल्लीगल मार्केट में पहुंच जाती है। ये दवा इतनी जहरीली होती है कि अगर इसकी मात्रा दो मिलिग्राम भी हो-मतलब एक पेंसिल की नोक जितनी तो इंसान की जान जा सकती है। यही वजह है कि अमेरिका में इससे मौतों का आंकड़ा हर साल नई ऊंचाई छू रहा है। 2022 और 2023 में ही 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत ऐसी ड्रंग्स से हुई जिनमें फेंटालिन मिला हुआ था।

कैसे घुसती है अमेरिका में ये जहर?

अब यहां आती है स्मार्ट स्मगलिंग की कहानी। चीन से सीधे अमेरिका में या फिर मेक्सिको के रास्ते ये ड्रग्स छोटे-छोटे पार्सलों में छिपाकर भेजे जाते हैं। इसका तरीका है मास्टर कार्टन शिपिंग। मतलब ये कि छोटे-छोटे बॉक्सेस को बड़े बॉक्स में पैक किया जाता है। ई-कॉमर्स और इंटरनेशनल शिपिंग में ये आम तरीका है लेकिन स्मगलर्स ने इसका बखूबी इस्तेमाल शुरू कर दिया है। Reuters की एक रिपोर्ट कहती है कि इसके अलावा, अमेरिका में एक नियम है de minimis rule, जिसके तहत अगर कोई पार्सल $800 से कम का है तो उस पर न टैक्स लगता है, न ड्यूटी और न ही कड़ी जांच। स्मगलर्स इसी का फायदा उठाकर जहर से भरे पार्सल अमेरिका भेजते हैं।

ये सिर्फ नशा नहीं, अमेरिका के लिए महामारी है

CDC (सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल) के अनुसार, अमेरिका में 2022 में 74,000 लोग सिर्फ सिंथेटिक ओपिऑइड्स जैसे फेंटानिल से मरे। ये आंकड़ा वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान के तीनों युद्धों में मारे गए अमेरिकियों से भी ज़्यादा है। 2012 के बाद से ये ड्रग अमेरिकी युवा पीढ़ी में सबसे बड़ी मौत की वजह बन गई है। 25 से 34 साल के लोगों की मौतों में एक-तिहाई फेंटानिल से हुई। और सबसे डरावनी बात ये है कि कई बार लोग गलती से भी इसका शिकार हो जाते हैं। उन्हें लगता है वे ज़ेनैक्स, ऑक्सीकोडोन जैसे ड्रग्स ले रहे हैं, लेकिन उसमें फेंटानिल मिला होता है।

कैसे बनती है फेंटानिल और कहां से आती है?

फेंटानिल को लैब में केमिकल्स को मिलाकर बनाया जाता है। यानी इसे पौधों से नहीं, बल्कि सिंथेटिक तरीके से तैयार किया जाता है। इसके लिए ज़रूरी केमिकल्स का सबसे बड़ा सप्लायर है चीन। हालांकि चीन ने 2019 में फेंटालिन को कंट्रोल्ड ड्रग्स की लिस्ट में डाला था लेकिन इससे जुड़े बहुत से केमिकल्स अभी भी अनकंट्रोल्ड है। कई बार इन केमिकल्स का इस्तेमाल दूसरे वैध कामें में भी होता है इसलिए कंपनिया आसानी से बच निकलती है। अमेरिकी जांच रिपोर्ट्स के मुताबिक, चीन की कुछ कंपनियां जानते हुए भी ऐसे केमिकल्स बेचती हैं जो फेंटानिल बनाने में इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद ये केमिकल्स मेक्सिको में भेजे जाते हैं, जहां अंडरग्राउंड लैब में ड्रग्स तैयार होती हैं। वहां से तस्करी के जरिए ये ड्रग अमेरिका पहुंचती है।

समस्या हल करने के लिए क्या किया गया है?

अमेरिका में ड्रग्स पर काबू पाने की सरकारी कोशिशें अक्सर नाकाम रही हैं। पहली बार 1890 में मॉर्फिन और अफीम पर टैक्स लगाया गया, लेकिन इसका उलटा असर हुआ। 1890 से 1902 के बीच कोकेन का इस्तेमाल 700% तक बढ़ गया। कोकेन इतना लोकप्रिय था कि इसे कोका-कोला जैसे ड्रिंक्स में भी मिलाया जाता था।

इसके बाद 1909 में अफीम स्मोकिंग पर बैन लगा, 1937 में मैरीजुआना टैक्स एक्ट आया और 1970 में कंट्रोल्ड सब्सटेंस एक्ट लागू हुआ। 1971 में राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने वॉर ऑन ड्रग्स का ऐलान किया, और 1986 में अमेरिकी कांग्रेस ने $1।7 अरब की लागत से एंटी-ड्रग अब्यूज़ एक्ट पास किया। इन सख्त कानूनों के बावजूद, ड्रग्स की सप्लाई और इस्तेमाल पर खास असर नहीं पड़ा, बल्कि इससे कई समुदायों, खासकर रंगभेद झेल रहे लोगों को भारी नुकसान हुआ।

बिहार में राष्ट्रपति शासन लगे...पटना के पारस अस्पताल गोलीकांड पर भड़के पप्पू यादव, कहा- बिहार में नीतीश नहीं, बीजेपी चला रही सरकार

नई दिल्ली, एजेंसी। बिहार के पटना के पारस अस्पताल में गुरुवार को एक मरीज पर चार बदमाशों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई। मरीज की मौके पर ही मौत हो गई। गोलियों की आवाज सुनकर अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि बदमाशों की गोलियों का शिकार हुए व्यक्ति पर भी हत्या का केस चल रहा था और वह पैरोल पर इलाज कराने के लिए जेल से बाहर आया था।

इसी बीच पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने घटनास्थल पर जाने की कोशिश की तो उन्हें पुलिस ने बाहर ही रोक दिया। इस बात से गुस्साए पप्पू यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में मरीज, नर्स, डॉक्टर कोई भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार की स्थिति को देखते हुए यहां राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। सांसद ने कहा कि यहां पर सरकार नीतीश नहीं बल्कि बीजेपी चलाती है।

'जाति को देखकर एनकाउंटर किए जाते हैं'

पप्पू यादव ने कहा कि अब बिहार में बाकी ही क्या रह गया। उन्होंने कहा कि जहां यह घटना हुई उससे 200 मीटर दूर क्वाटर है, बगल में थाना है। फिर भी यहां ऐसे दिनदहाड़े गोलियां चलाई जा रही हैं। उन्होंने नीतीश सरकार के नेताओं को घेरते हुए कहा कि बिहार में सिर्फ अब इन नेताओं की नेतानगरी ही बच गई है। ये लोग पैसों के बदौलत नेतानगरी करते हैं । राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए यादव ने कहा कि यहां जो भी एनकाउंटर होते हैं वह जाति के आधार पर होते हैं। गलत एनकाउंटर किए जाते है और इसके बाद सरकार एनकाउंटर करने वाले शूटर को बचाती है।

माफियाओं को पालने वाले माफिया राज खत्म करने की बात करते हैं

निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि सरकार माफिया राज खत्म करने की बात करती है, लेकिन यही लोग माफियाओं को पालते है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार तो सरकार चला नहीं रहे हैं, वह पूरी तरह से सो चुके हैं। सांसद ने कहा कि बिहार की सरकार बीजेपी और यहां के हेडक्वार्टर के अधिकारी चला रहे हैं।

राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की

सांसद ने कहा कि वह राज्यपाल ने उन्हें बुलाया है और वह राज्यपाल के कार्यालय जाकर उनसे अनुरोध करेंगे कि वह बिहार की स्थिति को देखते हुए यहां राष्ट्रपति शासन लगा दे। उन्होंने कहा कि साथ में हेडक्वार्टर में तैनात सभी पदाधिकारियों को यहां से हटा देना चाहिए और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। सांसद ने कहा कि इस हादसे के बाद हेडक्वार्टर के अधिकारियों को चुल्लू भर पानी में डूब कर जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीतीश तो सरकार चला नहीं रहे, इससे अच्छा यहां राष्ट्रपति शासन लग जाए। बता दें कि गुरुवार को चंदन मिश्रा नाम के एक व्यक्ति को बदमाशों ने अस्पताल में घुसकर गोली मार दी। चंदन की मौके पर ही मौत हो गई। चंदन पटना के ही आदर्श केंद्रीय कारा बेउर जेल में बंद था और उसके ऊपर हत्या का आरोप था। वह अपना इलाज करवाने पैरोल पर बाहर निकला था। इसी दौरान उसकी हत्या कर दी गई। कुछ दिन पहले बिहार में गोपाल खेमका की भी इसी तरह कुछ बदमाशों ने दिनदहाड़े गोली मारकर कर हत्या कर दी गई थी।

'बच्चे की कस्टडी पिता को देकर गलती हुई', SC ने मानी अपनी गलती ; 12 साल के मासूम की पीड़ा सुन पलट दिया फैसला

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने पिता-पुत्र कस्टडी को लेकर एक अहम आदेश सुनाया है। कोर्ट ने 12 वर्षीय लड़के की कस्टडी उसके पिता को सौंपने के अपने ही 10 महीने पुराने फैसले को पलट दिया।

कोर्ट ने कहा कि बच्चों की कस्टडी को लेकर अदालत के फैसले अंतिम नहीं हो सकते। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने कहा कि कस्टडी के दौरान बच्चे के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना की बच्ची की कस्टडी पिता को देकर अदालत ने गलती की है।

अब समझ लेते हैं कि मामला क्या है। दरअसल, बच्चे के माता-पिता की शादी 2011 में हुई थी और उसका जन्म 2012 में हुआ था। एक साल बाद दोनों अलग हो गए और बच्चे की कस्टडी मां को सौंप दी गई। मां ने 2016 में दोबारा शादी कर ली। उसके दूसरे पति के पहले विवाह से दो बच्चे थे, और नए जोड़े का अपना एक बच्चा था।

इसके बाद पिता ने बताया कि उन्हें 2019 तक बच्चे के ठिकाने के बारे में पता नहीं था, जब मां ने कुछ कागजी कार्रवाई के लिए उनसे संपर्क किया क्योंकि वह और उनके दूसरे पति बच्चों के साथ मलेशिया जाने का फैसला कर चुके थे। पिता ने यह भी बताया कि उन्हें पता चला कि बच्चे का धर्म उनकी सहमति या जानकारी के बिना हिंदू से ईसाई में बदल दिया गया था। इसके बाद पिता ने बच्चे की कस्टडी के लिए फैमिली कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उसे कोई राहत नहीं मिली। उन्होंने इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी। इसके बाद बच्चे की कस्टडी पिता को दे दी गई। हालांकि, मां ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन अदालत ने पिछले साल अगस्त में उनकी अपील खारिज कर दी थी। इसके बाद बच्चे की मां ने अदालत में एक नई अर्जी पेश की, जिसमें कहा गया कि हिरासत बदलने के आदेश की वजह से बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ा है। उनकी दलीलों को एक नैदानिक मनोवैज्ञानिक की रिपोर्ट का भी समर्थन प्राप्त था।

अपने जैविक पिता से बहुत कम बार मिला बच्चा

अदालत ने कहा कि जब बच्चा 11 महीने का था, तब दंपति अलग हो गए थे। तब से, बच्चा अपने जैविक पिता से बहुत कम बार मिला है और अपनी मां से दूर रहा है। अदालत ने अपने आदेश में कहा, ₹ऐसी परिस्थितियों में हिरासत बदलने का कठोर कदम का बच्चे पर बुरा असर पड़ा है। अदालत ने कहा कि पिता यह उम्मीद नहीं कर सकता कि इतने लंबे समय के बाद बच्चा उसके साथ अचानक माता-पिता जैसा रिश्ता बना लेगा। अदालत ने बताया कि पिता की कस्टडी में बच्चा काफी चिंता में था। आदेश में कहा गया है, ₹सौभाग्यपूर्ण परिणाम यह रहा है कि बच्चा, अपने प्ले स्कूल के दिनों से ही अपने सौतेले पिता को परिवार का हिस्सा मानता है और उन्हें अपने जीवन में एक अनिवार्य पिता के रूप में मानता है।

स्कूल से लौट रही नाबालिग का अपहरण के बाद यौन उत्पीड़न, पीछा करते हुए शख्स का वीडियो आया सामने

चेन्नई, एजेंसी। तमिलनाडु के गुम्मिडीपूंडी में एक 10 साल की नाबालिग छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। पुलिस ने गुरुवार को बताया कि स्कूल से घर लौट रही 10 साल की छात्रा का एक अज्ञात व्यक्ति ने अपहरण कर लिया और फिर उसका यौन उत्पीड़न किया।

पुलिस ने आगे बताया कि किशोर की उम्र मिड ट्वेंटीज यानी 20 से 25 साल के आसपास की मानी जा रही है। यह व्यक्ति गांव की सड़क पर उसका पीछा करता रहा। इसके बाद उस किशोर ने उस छात्रा का मुंह बंद कर दिया और उसे घसीटकर एक झाड़ी में ले गया। पुलिस ने बताया कि बाद में लड़की ने अपनी दादी को घटना की जानकारी दी और उन्होंने अपराधी का पता लगाने और उसे पकड़ने के लिए तलाश शुरू कर दी है।

लड़की को पहले पोन्नेरी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया और बाद में आगे के इलाज के लिए यहां के सरकारी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। उसके परिवार की शिकायत के बाद, पुलिस ने बीएनएस और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।

इब्राहिम ने शेयर की 'सरजमीं' की बीटीएस फोटोज, रूमर्ड गर्लफ्रेंड पलक तिवारी ने किया खास कमेंट

अपनी आगामी फिल्म 'सरजमीं' को लेकर चर्चाओं में बने इब्राहिम अली खान ने फिल्म से जुड़ी फोटोज शेयर की हैं।

सैफ अली खान के बेटे और एक्टर इब्राहिम अली खान इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 'सरजमीं' को लेकर चर्चाओं में बने हुए हैं। 'नादानियां' से डेब्यू के बाद ये इब्राहिम की दूसरी फिल्म है। इस फिल्म में इब्राहिम अपनी डेब्यू फिल्म से बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। अब इब्राहिम ने 'सरजमीं' की रिलीज से पहले फिल्म से जुड़ी कई बीटीएस तस्वीरें शेयर की हैं। इस पोस्ट पर इब्राहिम की रूमर्ड गर्लफ्रेंड पलक तिवारी ने कमेंट भी किया है।

अलग-अलग लुक में दिखे इब्राहिम

इब्राहिम ने अपने इंस्टाग्राम पर जो तस्वीरें शेयर की हैं। उनमें फिल्म से जुड़े उनके लुक की कई तस्वीरें भी हैं। कुछ एक तस्वीरों में इब्राहिम सेना की वर्दी पहने बंदूक चलाते दिख रहे हैं। जबकि कुछ तस्वीरें फिल्म के सेट के दौरान की हैं, जिनमें सिर्फ पेड़ और आसमान दिख रहा है। इस दौरान इब्राहिम ने कई सेल्फी भी पोस्ट की हैं और अपने अलग-अलग लुक को फ्लॉन्ट किया है।

पलक ने किया कमेंट

इब्राहिम की इस पोस्ट पर फैंस ने खूब कमेंट किए हैं। इनमें अधिकांश फैंस ने इब्राहिम को पापा सैफ की कार्बन कॉपी बताया है। इस बीच एक कमेंट जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा, वो था पलक तिवारी का। पलक तिवारी का नाम काफी लंबे वक्त से इब्राहिम के साथ जोड़ा जा रहा है। ऐसे में रूमर्ड गर्लफ्रेंड पलक का कमेंट अब चर्चा का विषय है। पलक ने कमेंट में सिर्फ स्टार वाला इमोजी बनाकर इब्राहिम को स्टार बताया है।

25 जुलाई को रिलीज हो रही है 'सरजमीं'

'सरजमीं' की बात करें तो इस फिल्म में इब्राहिम के साथ काजोल और पृथ्वीराज सुकुमारन प्रमुख भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म आतंकवाद पर आधारित मालूम पड़ती है। जिसमें एक आर्मी ऑफिसर का परिवार केंद्र में हैं। फिल्म में इब्राहिम काजोल के बेटे बने हैं। बोमन ईरानी के बेटे कायोज ईरानी द्वारा निर्देशित 'सरजमीं' 25 जुलाई को ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर रिलीज हो रही है।

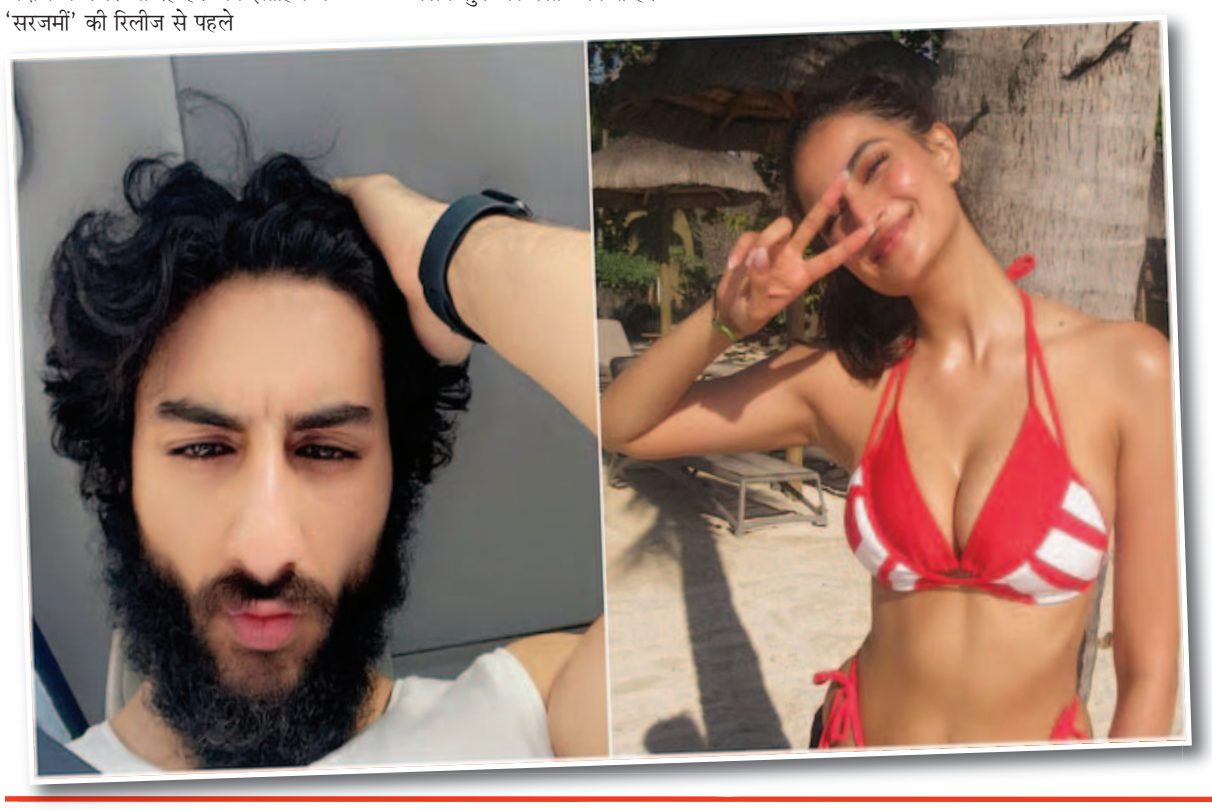

प्रियंका चोपड़ा ने निक के साथ बीच पर बनाई वीडियो, यूजर्स बोले- 'हम ऐसा ही प्यार चाहते हैं'

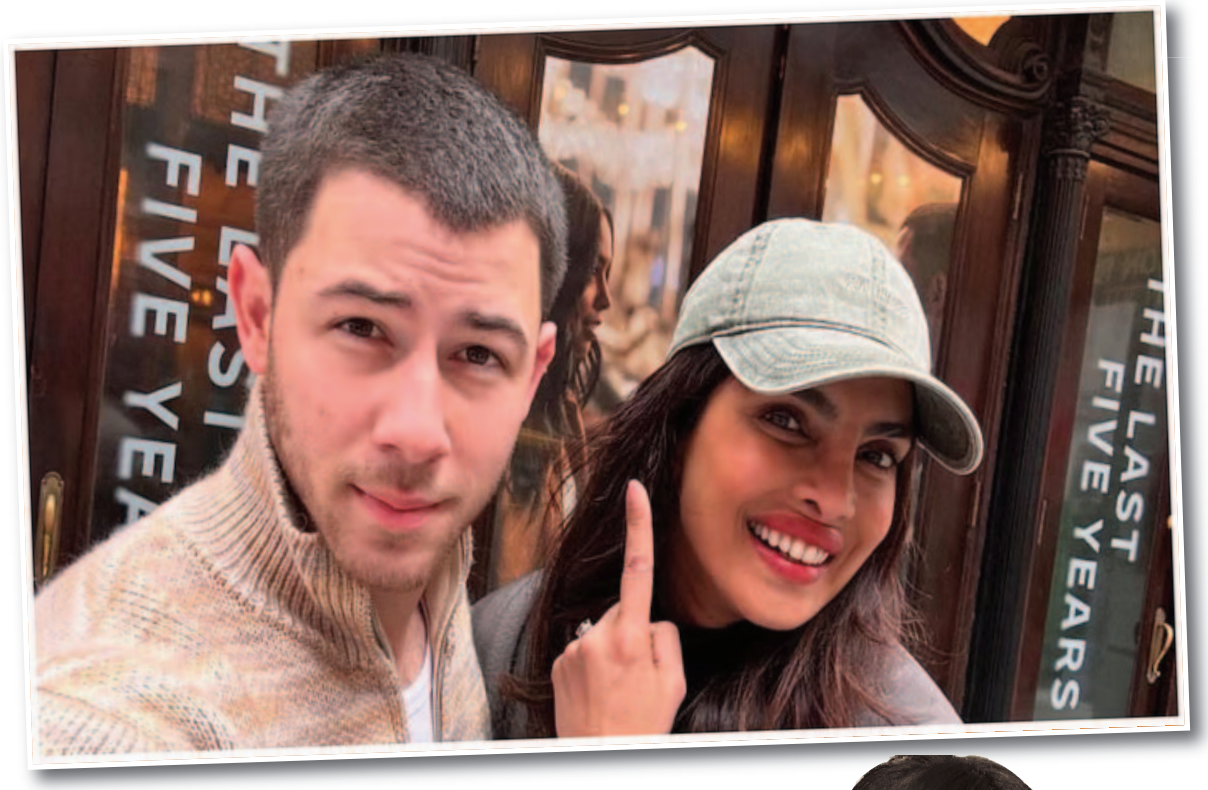

निक जोनस और प्रियंका चोपड़ा अपने नए रोमांटिक वेकेशन से इंटरनेट पर छाए हुए हैं। निक ने इंस्टाग्राम पर अपनी पत्नी के साथ एक खूबसूरत बीच वेकेशन का एक बेहतरीन वीडियो शेयर किया है। फैन्स इस जोड़ी की दिलकश केमिस्ट्री को देख कर वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं।

निक के वीडियो में क्या है?

जोनस ब्रदर्स के गाने 'आई कांट लूज' पर आधारित इस वीडियो के साथ निक ने कैप्शन दिया है, 'मैं गर्मी को ऐसे ही नहीं जाने दे सकता।' निक की वीडियो की शुरुआत निक के बीच पर उदास दिखने से होती है। वीडियो पर लिखा है 'उसके बिना।' हालांकि एक सेकंड बाद ही, प्रियंका चोपड़ा उनकी बाहों में दिखाई देती हैं, और वे धूप में स्विमवियर पहने हुए एक-दूसरे को चूमते, गले मिलते और हंसते हैं। इसके बाद इस वीडियो पर लिखा आता है 'उसके साथ।' फैंस को ये वीडियो पसंद आया है। वे वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं।

यूजर्स ने किए कमेंट

निक जोनस की वीडियो पर कमेंट करते हुए एक फैन ने लिखा है 'निकियांका, बहुत अच्छे कपल।' एक और यूजर ने लिखा है 'देसी गर्ल अपने पति के साथ अच्छा वक्त बिता रही है।' एक दूसरे यूजर ने लिखा है 'यही वो प्यार है जो हम सभी चाहते हैं!' एक और कमेंट इस तरह से है 'ये देसी गर्ल का असर है।' एक और यूजर ने लिखा है 'दोनों अपना कपल गोल सेट कर रहे हैं।'

निक ने प्रियंका की बनाई थी वीडियो

इस महीने की शुरुआत में, निक और प्रियंका ने लंदन में उनकी अमेजन प्राइम वीडियो एक्शन-कॉमेडी, 'हेड्स ऑफ स्टेट' के प्रीमियर में सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। एक बैंगनी रंग के गाउन में, प्रियंका ने 'बैम बैम' गाने पर डांस किया। इस वीडियो को निक ने मोहब्बत से फिल्माया था। उन्होंने वीडियो पर लिखा, 'लंदन में हेड्स ऑफ स्टेट के प्रीमियर के लिए डेट नाइट।' वीडियो के आखिर में दोनों एक दूसरे से प्यार से गले मिले।

प्रियंका का काम

आपको बता दें आखिरी बार प्रियंका चोपड़ हॉलीवुड फिल्म 'हेड्स ऑफ स्टेट' में नजर आईं। इसमें उनके साथ इदरीस एल्बा और जॉन सीना भी हैं। यह फिल्म ब्रिटिश प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच एक अप्रत्याशित गठबंधन पर आधारित है। फिल्म में प्रियंका एक खतरनाक एमआई6 एजेंट की भूमिका निभा रही हैं।

स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक प्रभात पांडेय द्वारा साई ऑफसेट प्रिंटर्स 40, वासुदेव भवन कैसरबाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 2/74, विक्रांत खंड, गोमती नगर, लखनऊ से प्रकाशित । शाखा कार्यालय: S-15/109, सेक्टर -15, इंदिरा नगर, लखनऊ। समस्त लेख, रचनाओं एवं विज्ञापन में लेखन और विज्ञापनदाताओं के अपने विचार हैं। इसके लिए आर्यावर्त क्रांति की कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र लखनऊ, उत्तर प्रदेश ही होगा। RNI No: UPHIN/2014/57034 Website : aryavartkranti.com
*सम्पादक: प्रभात पांडेय सम्पर्क: 9839909595, 8765295384 Email: aryavartkrantidainik@gmail.com